सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 174, नई दिल्ली । मंगलवार, 03 सितम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा।

03 सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड दिल्ली आपातकालीन प्रतिक्रिया और सीपीआर प्रदर्शन पर विशेष सत्र

06 चीन से घटाना होगा व्यापार घाटा

08 "हमारे देश में ऊंच-नीच, भेद-भाव और जातिवाद आज़ केंसर से भी बड़ी घातक"

दिल्ली में व्यावसायिक गतिविधि के लिए पंजीकृत और आने वाले समय में पंजीकरण करवाने वाले वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग दुनिया का पहला ऐसा परिवहन विभाग बनने जा रहा है जहा व्यावसायिक गतिविधि में शामिल वाहनों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , माननीय उच्चतम न्यायालय भारत, माननीय उपराज्यपाल, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली सरकार और स्वयं परिवहन विभाग द्वारा आदेशित/ निर्देशित परमिट कंडीशन की कोई कीमत या डर नही रहेगा। इसका अर्थ यह है की दिल्ली में पंजीकृत व्यावसायिक गतिविधि में शामिल वाहनों पर इन सबके द्वारा जारी नियमों/ कानूनों को जांच करने वाला ही कोई नही रहेगा। यानी अभी तो दिल्ली में विशेष परिवहन आयुक्त प्रवर्तन शाखा और प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों के कारण दिल्ली में इतने अनाधिकृत गतिविधि में शामिल वाहन चल रहे हैं जो जनता की सुरक्षा के लिए खतरा है और अब जल्द ही दिल्ली में जो थोड़ी सी नियम कानून व्यवस्था बची हुई है वह भी पूरी तरह चरमरा जाएगी और आपकी जानकारी के लिए बता दे की उसके लिए विशेष परिवहन आयुक्त द्वारा तकनीकी शाखा में आसिन किए गए गैर तकनीकी अधिकारी जो असल में सख्यिकी विभाग का अधिकारी है द्वारा बना कर चलवाई गई फाइल पर विशेष परिवहन आयुक्त के अनुमोदन पर आयुक्त परिवहन द्वारा बैठक कर जल्द फैसला करने की घोषणा कर दी गई है। आपकी जानकारी हेतु बता दे विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है की इस कार्य को परिवहन मंत्री द्वारा भी हरी झंडी दिखा दी गई है। इस आदेश के जारी होते ही दिल्ली वासियों को व्यावसायिक गतिविधि में शामिल अनाधिकृत वाहनों की उपलब्धि में कोई कमी नहीं आएगी वह अलग बात है की उनमें सफर करते हुए आप कितने सुरक्षित रहेंगे पर आज की तारीख में यह तो पहले से ही सिद्ध हो चुका है की परिवहन विभाग के आला अधिकारी और दिल्ली सरकार मे परिवहन मंत्री को जनता की सुरक्षा से कुछ भी लेना देना नहीं है। **इसी के तहत दिल्ली सरकार ने अपने पूरे कार्यकालो में दिल्ली की जनता को एक भी बस या कोई वाहन सार्वजनिक सवारी सेवा के लिए खरीद कर नही दिया और साथ ही दिल्ली को सुरक्षित सवारी सेवा**

प्रदान करने वाली दिल्ली परिवहन निगम को पंगु बना कर रख दिया और गैर कानूनी तरीके से उसकी संपत्ति को प्राईवेट बस ऑपरेटर्स को सुपुर्द करवाते जा रही है। वही परिवहन विभाग के आला अधिकारी तकनीकी पदों पर गैर तकनीकी अधिकारियों को आसिन करते जा रहे हैं। अब जल्द ही दिल्ली सरकार दुनिया के समक्ष विज्ञापनों द्वारा अपने आप को सुर्खियों मे आता नजर आएगा "**दिल्ली परिवहन विभाग दुनिया का पहला परिवहन विभाग जहां एक भी तकनीकी अधिकारी कार्यरत नहीं और व्यावसायिक गतिविधि में शामिल वाहन मालिकों के खिलाफ जांच करने वाला भी कोई नहीं**"

साथ ही यह भी नजर आएगा की **किसी भी श्रेणी के परमिट धारक को वाहन पंजीकरण के लिए उस पर मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के अनुसार कुछ भी लगवाने या करवाने की आवश्यकता नहीं।** जो वाहन डीलर ने वाहन दे दिया वहीं पंजीकृत और उसी पर परमिट उपलब्ध। धन्य है दिल्ली का परिवहन विभाग जिसने वाहन मालिकों के प्रति इतनी हमदर्दी दिखाई।

'परिवहन विशेष' दैनिक समाचार पत्र में 2 सितंबर के अंक में प्रकाशित खबर "दिल्ली की जनता और परिवहन विशेषज्ञों से राय की अपील" पर संज्ञान लेते हुए टोलवा ने ट्विटर के माध्यम से दिल्ली परिवहन विभाग में विशेष परिवहन आयुक्त शहजाद आलम के द्वारा कार्यकाल में जनहित और विभागीय कार्यों के प्रति जारी आदेशों/ दिशानिर्देशों की निष्पक्ष जांच हेतु गृह मंत्री भारत सरकार से निवेदन किया।

बॉर्डर पर नया बस अड्डा बनने से सुधरेंगे कश्मीरी गेट आईएसबीटी के हालात, एलजी की मिली मंजूरी

कश्मीरी गेट आईएसबीटी को हटाने की अटकलों पर विराम परिवहन विभाग ने दी सफाई। अंतर्राज्यीय रूटों पर चलने वाली जम्मू हिमाचल हरियाणा पंजाब चार राज्यों की बसें अब कश्मीरी गेट नहीं आएंगी। इन बसों के लिए बाहरी पश्चिमी दिल्ली में स्थित टीकरी बॉर्डर पर नया आईएसबीटी बनेगा। इस कदम से कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर बसों और यात्रियों का दबाव आधा रह जाएगा।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर गत दिनों हुई एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक के बाद से कश्मीरी गेट आईएसबीटी हटाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मगर परिवहन विभाग ने साफ किया है कि इस आईएसबीटी हटाया नहीं जाएगा बल्कि यहां बसों का दबाव कम किया जाएगा।

इसके लिए अंतर्राज्यीय रूटों पर चली रहीं जम्मू, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब चार राज्यों की बसें इस आईएसबीटी में नहीं आएंगी। योजना के तहत इसके लिए बाहरी पश्चिमी दिल्ली में स्थित टीकरी बॉर्डर पर नया आईएसबीटी बनेगा। परिवहन विभाग का आंकलन है कि इससे इस आईएसबीटी पर बसों और यात्रियों का दबाव आधा रह जाएगा।

काफी पुराना है यह बस अड्डा

महाराणा प्रताप कश्मीरी गेट अन्तर्राज्यीय बस अड्डा (आईएसबीटी) 1976 से चल रहा है। यह भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े अन्तर्राज्यीय बस अड्डों में से एक है। यह लगभग 13 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां से जम्मू, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी बसें आवागमन करती हैं। इसके अलावा शहर के लिए सिटी बस सेवा की भी बसें यहां से चलती हैं।

हर दिन डेढ़ लाख लोग करते हैं आवागमन

ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली विभिन्न शहरों के लिए जाने वाली निजी बसें भी यहां से

चलती हैं। कुल मिलाकर वर्तमान में इस आईएसबीटी से प्रतिदिन 2600 से अधिक बसों का संचालन होता है। इसमें करीब 1300 इंटरस्टेट बसें, 1200 डीटीसी व क्लस्टर बसें और लगभग 100 ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसें शामिल हैं। यहां से प्रतिदिन डेढ़ लाख से अधिक लोग आवागमन करते हैं।

यातायात की समस्या है गंभीर

यहां भारी आवागमन के चलते इस इलाके में यातायात की गंभीर समस्या बनी हुई है। इसकी वजह से आसपास के दूसरे क्षेत्रों जैसे पुल बंगश, सब्जी मंडी, आजाद मार्केट, सदर बाजार और मलका गंज का यातायात भी प्रभावित होता है।

टीकरी बॉर्डर पर बस अड्डे की मिली अनुमति

यहां का दबाव कम करने के लिए टीकरी बॉर्डर पर जिस नए आईएसबीटी को बनाया जाना है। वहां सात एकड़ में नया बस अड्डा बनेगा। उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने इसकी अनुमति दे दी है। इसके बाद परिवहन विभाग ने इसके लिए जमीन हासिल करने के लिए लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा है।

यह जमीन लोक निर्माण विभाग की है। परिवहन विभाग का मानना है कि चार राज्यों की बसें कश्मीरी गेट नहीं आने से सड़कों पर भी दबाव कम होगा और पूरे कश्मीरी गेट इलाके में यातायात दबाव कम हो जाएगा।

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि भविष्य में इस आईएसबीटी से दूसरे राज्यों के लिए चलने वाली आल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली सभी बसें यहां से ही चलाए जाने की योजना है ।जिससे दिल्ली में जगह जगह से इन बसों का संचालन बंद किया जाएगा।

राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट प्रक्रिया डिप्टी सीएम ने आदेश कर करवाई बंद, कारण जानकर हों जाएंगे आप हैरान

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट प्रक्रिया डिप्टी सीएम ने आदेश कर करवाई बंद, कारण जानकर हों जाएंगे आप हैरान इसे कहते है जनहित में दिया आदेश जो दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी कभी भी नहीं करे।

राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने परिवहन विभाग की ओर से वाहनों में लगवाई जा रही हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट (एचएसआरपी) प्रक्रिया बंद करने के निर्देश जारी किए है। राजस्थान में परिवहन विभाग की ओर से वाहनों में लगवाई जा रही हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट (एचएसआरपी) पर विभाग के ही परिवहन मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्री ने परिवहन विभाग की एसीएस को पत्र लिखकर वाहनों में नम्बर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया को बंद करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि जिन वाहनों की बुकिंग हो चुकी है, आगामी पांच दिन में अधिक से अधिक वाहनों में नम्बर प्लेट लगाकर प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए। इसी के साथ जिन वाहन मालिकों ने स्लॉट ले रखे हैं और नम्बर प्लेट नहीं लगी है, उनके बुकिंग का भुगतान वापस किया जाए। मंत्री बैरवा ने नए सिरे से विभाग स्तर पर वाहनों में

नम्बर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करने के लिए कहा है।

इसीलिए बन्द करने के निर्देश मंत्री ने पत्र में कहा है कि वर्तमान में परिवहन विभाग सियाम पोर्टल के जरिए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवा रहा है। सियाम राष्ट्रीय स्तर का पोर्टल है, जिसका इस्तेमाल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किया जाता है। राजस्थान में इस पोर्टल के जरिए नम्बर प्लेट लगवा रहे हैं। वाहन कंपनियां इस पोर्टल के जरिए आने वाले एप्लिकेशन के आधार पर नंबर प्लेट लगाती हैं। मंत्री का तर्क है की इस प्रक्रिया के तहत वाहन मालिकों को कई महीनों आगे के स्लॉट बुक किए जा रहे हैं और अधिक राशि की वसूली की जा रही है। इससे आमजन को परेशानी हो रही है। मंत्री ने विभाग स्तर पर अपनी अलग प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।15 लाख से अधिक वाहनों मालिकों ने बुक किए स्लॉट

परिवहन विभाग ने दिसंबर 2023 से वाहनों ने हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन जून 2024 तक राज्य में महज 3.33 लाख वाहन चालकों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन किया। इसके बाद विभाग ने 31 जुलाई तक आवेदन की तिथि बढ़ा दी। कम आवेदन आने के कारण मंत्री के निर्देश पर 10 अगस्त तक और तिथि बढ़ाई थी। इस दिन तक करीब 15 लाख वाहन मालिकों ने नम्बर प्लेट के लिए अवेदन किया। जबकि करीब 25 लाख वाहनों में एचएसआरपी लगनी हैं। लेकिन धीमी प्रक्रिया के कारण कम वाहनों में ही प्लेट लगवाई गई। मंत्री ने 5 दिन के बाद वाहन मालिकों को बुकिंग के पैसे वापस करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में 10 लाख से अधिक वाहनों को पैसे रिफंड करने होंगे।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020) , एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में कितना आया बदलाव?

शालिनी बाजपेयी

धरती के इस छोर से उस छोर तक
मुट्ठी भर सवाल लिये मैं
छोड़ती-हाँफती-भागती
तलाश रही हूँ सदियों से निरंतर
अपनी ज़मीन, अपना घर
अपने होने का अर्थ!

भारतीय समाज की नारी की स्थिति को बखूबी बयां करती निर्मला पुतुल की ये पंक्तियाँ पूरे समाज की व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती हैं। भले ही आज हम यह कहकर अपनी पीठ थपथपा लें कि आजादी के 75 सालों में हमारी महिलाएँ चाँद पर पहुँच गई हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, ओलंपिक में पदक जीत रही हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ चला रही हैं या राष्ट्रपति बनकर देश की बागडोर संभाल रही हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर देखें तो यह संख्या महिलाओं की आबादी का अंशमात्र ही है। हमारे समाज की महिलाओं का एक बड़ा तबका आज भी सामाजिक बंधनों की बेड़ियों को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाया है; उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है या यूँ कहें कि हमारा पितृसत्तात्मक समाज उन्हें जन्म से ही ऐसे साँचे में ढालने लगता है कि वे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिये पुरुषों का सहारा ढूँढती हैं। वहीं यह भी सत्य है कि "जब-जब कोई स्त्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है तब-तब न जाने कितने रीति-रिवाजों, परंपराओं, पौराणिक आख्यानों की दुहाई देकर उसे गुमनाम जीवन जीने पर विवश कर दिया जाता है।" इसलिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर भारत में शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक स्तर पर महिलाओं ने अब तक कितनी दूरी तय की है-

कितनी बढ़ी महिलाओं की साक्षरता दर?

भारत में आज भी बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं, जो शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। वहीं, पढ़ाई-लिखाई के दौरान बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाली लड़कियों की संख्या भी लड़कों की संख्या से बहुत ज़्यादा है क्योंकि लड़कियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे घर के कामकाज में मदद करें। वहीं, उच्च शिक्षा की बात करें तो बहुत सी लड़कियाँ सिर्फ इसलिए उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं क्योंकि उनके परिवार वाले पढ़ाई के लिये उन्हें घर से दूर नहीं भेजते हैं, जिसके चलते उनका अधिकतर समय घरेलू कामों में खर्च होता है और महिलाओं व पुरुषों के बीच समानता का अंतराल बढ़ता चला जाता है। इससे इस मिथक को बढ़ावा मिलता है कि, शिक्षा-दीक्षा लड़कियों के किसी काम की नहीं है क्योंकि अंत में उन्हें प्राथमिक रूप से घर ही संभालना है, शादी करनी है और पति व बच्चों की सेवा करनी है। इतना ही नहीं, लड़कियों को शादी कब करनी है, किससे करनी है, बच्चे कब पैदा करने हैं? ये सब कुछ भी हमारी पितृसत्ता तय करती है।

आँकड़ों पर नजर डालें तो, साल 1951 में भारत की साक्षरता दर केवल 18.3 फीसदी थी जिसमें से महिलाओं की साक्षरता दर 9 फीसदी से भी कम थी। वहीं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के डाटा के अनुसार साल 2021 में देश की औसत साक्षरता दर 77.70 प्रतिशत थी जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 84.70 प्रतिशत, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 70.30 प्रतिशत थी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आजादी के बाद से अब तक महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। निम्नलिखित पंक्तियाँ देश की बेटियों को एक बार फिर से उठ खड़े होने का ज़ज्बा प्रदान करती हैं-

आओ उड़ाने भरें
पंख भी हैं, खुला आकाश भी है
फिर ये न उड़ पाने की मज़बूरी कैसी
लगता है, आत्मा पर जंग लगे संस्कारों की
कील ठोंक दी गई है
कि पंख बस
यूं ही फड़फड़ाएं और रह जाएं

रसोई में केवल महिलाएँ ही क्यों?

भारत के रसोइघरों से महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज भी घर की बेटी, बहू, माँ व पत्नी चाहे कितनी भी पढ़ी-लिखी क्यों न हो; कितने ही बड़े पद पर काम क्यों न कर रही हो; घर के सभी सदस्यों के लिये खाना पकाने व परोसने की उम्मीद सिर्फ महिला सदस्य से ही की जाती है। इसी वजह से भारतीय समाज में लड़कियों को बचपन से ही रसोईघर के काम सिखाने शुरू कर दिए जाते हैं, जबकि लड़कों को रसोई से दूर रखा जाता है। जिससे आगे चलकर वे लड़के, जिनसे कभी रसोई के काम नहीं करवाए गए; जिन्होंने कभी अपने पिता को माँ के साथ खाना बनाते या अन्य घरेलू कामों में मदद करते नहीं देखा, वे भी अपने बच्चों को वैसा ही बनाते हैं जैसा उन्होंने अपने परिवार में देखा होता है। जिससे पितृसत्ता की विचारधारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना किसी रुकावट के स्थानांतरित होती रहती है और अधिकांश महिलाएँ पूर्ण रूप से देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे पाती हैं।

यहाँ पर इस बात पर भी विचार करना ज़रूरी है कि, महिलाएँ घर के पुरुषों को खाना खिलाने के बाद अंत में खाना खाती हैं। घर का कोई पुरुष इस बारे में नहीं सोचता कि उन्हें भी हमारे साथ बैठकर खाने का अधिकार है। इसका यह मतलब नहीं कि सभी पुरुष क्रूर और हिंसक है। इसका मतलब यह है कि, पितृसत्ता ने हमें ऐसा बना दिया है कि हम उससे परे जाकर सोच नहीं पाते हैं। जिसमें बदलाव की ज़रूरत है। इस संदर्भ में निर्मला पुतुल की निम्नलिखित पंक्तियाँ बेहद प्रासंगिक हैं-

तन के भूगोल से परे
एक स्त्री के
मन की गाँठें खोलकर
कभी पढ़ा है तुमने
उसके भीतर का खौलता इतिहास?
XXXX
अगर नहीं!
तो फिर जानते क्या हो तुम
रसोई और बिस्तर के गणित से परे
एक स्त्री के बारे में...?

धर्मों में भी महिलाओं का स्थान निम्न

भारत जैसे पितृसत्तात्मक देश में शिक्षा, मीडिया, कानूनी संस्थाएँ, आर्थिक संस्थाएँ, राजनीतिक संस्थाएँ सभी पूरी तरह से पितृसत्तात्मक हैं। यहाँ तक कि, सभी धर्म भी पितृसत्तात्मक हैं। अधिकांश धर्म महिला को अपना मुख्य आराध्य नहीं मानते। चूंकि धर्मों में पितृसत्ता को सर्वोच्च दिखाया गया है इसलिए महिलाओं को हमेशा से धर्म के नाम पर दबाने का प्रयास किया जाता है, और महिलाएँ बिना बराबरी का अधिकार माँगे अपने पति को परमेश्वर, स्वामी मानने लगती हैं। वह इस बात पर ज़रा भी विचार नहीं करतीं कि पति-पत्नी में अगर एक मालिक है तो दूसरा कौन होगा? वह आसानी से अपने आपको गुलाम मान लेती हैं क्योंकि उनका प्राइमरी स्कूल जो कि उनका परिवार होता है, में उन्हें बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है।

फीसदी महिलाएँ हैं, जबकि संसद में महिलाओं की वैश्विक औसत भागीदारी 25 फीसदी से ज़्यादा है। इसके अलावा, ग्रामीण अंचलों में पंचायत स्तर पर अधिकांश महिलाओं को केवल मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया जाता है यानी चुनाव तो महिला जीतती है लेकिन सत्ता से संबंधित सभी निर्णय उसके परिवार के पुरुष सदस्य करते हैं।

वहीं, न्यायालय में भी महिलाओं की संख्या संतोषजनक नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के सर्वोच्च न्यायालय सहित उच्च न्यायालयों में मौजूद न्यायाधीशों में महज 11 प्रतिशत महिलाएँ हैं। समय की माँग है कि अब महिलाएँ जाग्रत हों और अपनी क्षमता को पहचान कर, परंपरागत रूढ़ियों को खंडित कर देश की मुख्यधारा में अधिक से अधिक योगदान दें।

ऐ शक्ति स्वरूपा
ऐ भावी पीढ़ी की निर्माता
मानवता तुम्हे प्रणाम करे
आओ! उड़ान भरें
आओ! हम सब मिलकर इस पार
बादलों के उस पार
लंबी-ऊंची उड़ान भरें

निष्कर्ष

रूप में हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में एक लंबा रास्ता तय किया है, परंतु अभी भी मंजिल से मीलों दूर हैं। तेजी से भागते समय के इस पहिये के साथ हमारी रफ्तार बहुत धीमी है, और इस रफ्तार को तभी बढ़ाया जा सकता है जब भारतीय समाज पितृसत्तात्मक मानसिकता से ऊपर उठकर महिलाओं को भी पुरुषों के समान बराबरी के अधिकार प्रदान करेगा। हालाँकि हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं लेकिन यहाँ का समाज अपने नियमों के अनुसार, महिलाओं को संचालित करता है, जिसमें बदलाव की सख्त ज़रूरत है।

साथ ही, इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिये कि हमें नारीशक्ति का उद्धारक नहीं, वरन उनका सहायक बनना है। भारतीय महिलाएँ भी संसार की अन्य महिलाओं की तरह अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता बस इतनी है कि उन्हें उपयुक्त अवसर प्रदान किए जाएँ; उनका वस्तुकरण करने की बजाय उन्हें मनुष्य समझा जाए। बेहतरीन कवयित्री अनामिका ने स्त्रियों को गहराई से समझने की गुजारिश करते हुए लिखा है-

सुनो, हमें अनहद की तरह
और समझो जैसे समझी जाती है
नई-नई सीखी हुई भाषा।

आर्थिक रूप से कितनी सक्षम हैं भारतीय महिलाएँ

आज भी महिलाओं की अधिकांश समस्याओं का कारण आर्थिक रूप से परनिर्भरता है। यह बेहद चिंताजनक है कि देश की कुल आबादी में 48 फीसदी महिलाएँ हैं जिसमें से मात्र एक तिहाई महिलाएँ रोजगार में संलग्न हैं। इसी वजह से भारत की जीडीपी में महिलाओं का योगदान केवल 18 फीसदी है।

यदि परिवार के भीतर और बाहर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावों को समाप्त कर पुरुषों के समान अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने के अवसर प्रदान किए जाएं तो अन्य महिलाएँ भी गीता गोपीनाथ, इंद्रा नुई, किरण मजूमदार शॉ की तरह सशक्त होंगी, साथ ही देश भी आर्थिक मोर्चे पर तेजी से प्रगति करेगा। सभी महिलाओं को इन चार पंक्तियों को ज़रूर आत्मसात करना चाहिये-

न रहो कभी किसी की आश्रिता,
खुद बनकर स्वावलंबी बनो हर्षिता
हमें खुद अपना संबल बनना है
हमें परजीवी लता नहीं बनना है॥

सत्ता व न्यायालयों में महिलाओं की भागीदारी

इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के समय में महिलाएँ घर की चारदीवारी से निकलकर सत्ता की बागडोर संभाल रही हैं, और न केवल संभाल रही हैं बल्कि कुशल संचालन कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ममता बनर्जी, प्रियंका गाँधी, स्मृति ईरानी, मेनका गाँधी, मायावती को देखा जा सकता है। लेकिन देश में महिलाओं की आबादी के अनुसार देखें तो राजनीति में महिलाओं की संख्या अभी भी काफी कम है। भारतीय संसद में केवल14

शालिनी बाजपेयी
शालिनी बाजपेयी यूपी के रायबरेली जिले से हैं। इन्होंने IIMC, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा करने के बाद जनसंचार एवं पत्रकारिता में एम.ए. किया। वर्तमान में ये हिंदी साहित्य की पढ़ाई के साथ साथ लेखन का कार्य कर रही हैं।

नए रिलेशनशिप में रखने जा रहे कदम, तो आज ही इन 7 आदतों को करें टाटा-बाय

नए-नए रिलेशनशिप में कई बार लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि रिश्ता शुरू होने से पहले की खत्म हो जाता है। अगर आप भी बीते कल को भुलाकर अपनी जिंदगी में एक नए शख्स को जगह दे रहे हैं तो जरूरी है कि इससे पहले ही आप कुछ आदतों को गुडबाय बोल दें। आइए इस आर्टिकल में आपको ऐसी 7 गलतियां (Relationship Advice) बताते हैं।

नए-नए रिश्ते में आमतौर पर लोग ये सोचकर कदम रखते हैं कि इस हर हाल में खुशनुमा और सफल बनाकर रहेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, जिससे रिश्ता कमजोर हो और दोबारा अकेलेपन से जूझना पड़े। हालांकि कई लोग बीते कल से सीख लेने के बावजूद नए रिलेशनशिप (Tips For New Relationship) में आने के बाद भी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो अच्छे भले रिश्ते को शुरू होने पर पहले ही बिगाड़ कर देती हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसी 7 आदतें (Relationship Bad Habits), जिन्हें नए रिश्ते में बंधने से पहले आपको छोड़ देना चाहिए।

1) बीते कल को लेकर रोना

पास्ट के बारे में रोना एक आम आदत है, लेकिन यह आपके वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए मुसीबत बन सकता है। अतीत में हुए नुकसान या दर्द पर ध्यान लगाने के बजाय आपको आज में जीने और अपने नए पार्टनर के साथ अच्छी यादें बनाने पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

2) विश्वास की कमी

बिना विश्वास का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है। ऐसे में, अगर आप भी शक का चश्मा पहनकर नए रिलेशनशिप में कदम रखने की सोच रहे हैं, तो संभल जाइए। साथी पर भरोसा नहीं करते हैं, तो यह आपके रिश्ते में स्ट्रेस की वजह बन सकता है।

3) कम्युनिकेशन की कमी

कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते की नींव है। अगर आप अपनी भावनाओं और जरूरतों को अपने पार्टवर के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो गलतफहमी और संघर्ष पैदा हो सकता है। बिना तोल-मोल किए साफ शब्दों में अपनी बात को रखने की आदत डालें और अपने साथी की बात सुनने के लिए समय भी निकालें।

4) जरूरत से ज्यादा निर्भर

एक हेल्दी रिश्ते में, दोनों पार्टनर स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होने चाहिए। जरूरत से ज्यादा निर्भरता आपके साथी पर दबाव डाल सकती है और आपके रिश्ते का बैलेंस बिगाड़ सकती है। आप अगर अपने स्वयं के हितों और लक्ष्यों को ठीक ढंग से समझ लेते हैं और अपने पार्टनर को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो इतना भी बेहद फायदेमंद हो सकता है।

5) एक्स के साथ तुलना

अपने नए पार्टनर की तुलना अगर आप एक्स के साथ करते हैं, तो ये आपकी एक बड़ी गलती है। किसी भी रिश्ते की अपनी खूबियां और चुनौतियां होती हैं जिसे लेकर दोनों लोग जिम्मेदार होते हैं, इसलिए एक्स को कोसने के बजाय अब आपको इस एक्सपीरिएंस को एक अच्छी सीख के तौर पर लेना चाहिए।

6) जरूरत से ज्यादा खिंचाई

दोष हर किसी में होते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपने पार्टनर की कमियों को भी स्वीकार करें। जरूरत से ज्यादा खिंचाई करना रिश्ते में तनाव और संघर्ष को पैदा करता है। इसके बजाय जब आप रिश्ते में आ ही गई हैं, तो अब अपने पार्टनर की तारीफ करने और उनके गुणों पर ध्यान देने की कोशिश ज्यादा करें।

7) दवाब बनाना

एक हेल्दी रिश्ते में, फ्रीडम बेहद जरूरी होती है। अगर आप अपने पार्टनर को कंट्रोल में लेने जैसी कोशिशें कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी शुरुआत नहीं है। अपने साथ-साथ आपको सामने वाले शख्स की फीलिंग्स की भी कद्र करनी चाहिए।

"विधायक अमानतुल्लाह खान को जबरदस्ती झूठे मामले में फसाने की साजिश की जा रही"

सुषमा रानी

नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, कि आज सुबह लगभग 6:15 बजे केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी, ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर छापा मारने पहुंची थी और अब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है I उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है, कि किस तरह से खुल्लम-खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है I सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जानबूझकर वक्फ बोर्ड में पैसे लेकर भर्ती करने का एक झूठा और आधारहीन कैसे बनाया गया है और उसमें आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को फसाया गया I उन्होंने कहा कि 2016 में यह मामला बनाया गया और पहले तो केंद्र सरकार की ओर से खूब शोर मचाया गया, कि भ्रष्टाचार हुआ है और ACB जांच कर रही है, परंतु केंद्र सरकार के षड्यंत्र की और ACB द्वारा दाखिल किए गए कैसे की धज्जियां कोर्ट में उस वक्त उड़ गई, जब कोर्ट ने इस मामले में अमानतुल्लाह खान को यह कहते हुए जमानत दे दी, कि आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से, तथ्यों से कहीं पर भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, कि पैसे लेकर वक्फ बोर्ड में किसी को कोई नौकरी दी गई है I

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार ने विधायक अमानतुल्लाह खान को जबरदस्ती झूठे केस में फसाने की कोशिश की I पहले ACB ने फिर CBI ने अमानतुल्लाह खान के घर पर छापा मारा, फिर उन्हें गिरफतार भी किया गया, परंतु कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए और अदालत से उन्हें ज़मानत मिल गई I अब जब ACB और सीबीआई इस मामले में कुछ नहीं कर सकी तो अमानतुल्लाह खान को फसाने के लिए भाजपा शासित केंद्र सरकार ने इस बार ईडी का सहारा लिया है I कभी अखबारों में कभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनको बदनाम किया गया I परंतु फिर भी जनता का आशीर्वाद उन्हें दोबारा प्राप्त हुआ और वह दोबारा से भारी मतों से जीतकर आए I उन्होंने कहा कि जब ACB से बात नहीं बनी तो वही सड़ा गला और झूठा मामला सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया I इस मामले में फिर सीबीआई के द्वारा जांच प्रक्रिया की गई और सीबीआई ने अपनी चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की I सीबीआई के मामले में भी कोर्ट में भाजपा शासित केंद्र सरकार इस बात को साबित करने में विफल रही की विधायक अमानतुल्लाह खान ने पैसे लेकर वक्फ बोर्ड में किसी को नौकरी देने का काम किया है I सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब ACB और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसियों के माध्यम से भाजपा शासित केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को झूठे मामले में फंसाने में असफल रही, तो उन्होंने अपनी तीसरी जांच एजेंसी ईडी को इस काम पर लगा दिया I यह पहली बार नहीं है कि ईडी ने अमानतुल्लाह खान के घर पर छापा मारा है, इससे पहले भी ईडी उनके घर पर छापा मार चुकी है I न केवल घर पर छापा मारा बल्कि उन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर घंटो तक पूछताछ भी कर चुकी है I ईडी ने भी विधायक अमानतुल्लाह खान के घर रात में छापा मारा, घंटो तक पूछताछ चली, और आज उसी श्रंखला को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर ईडी ने अमानतुल्लाह खान के घर पर छापा मारा और अंततः आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया I सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह घटना साफ तौर पर इस बात को दर्शाती है की ईडी का मकसद केवल और केवल आम आदमी पार्टी के विधायकों, नेताओं और मंत्रियों को किसी भी हालत में गिरफ्तार करना है और यही कारण है कि आज अमानतुल्लाह खान को भी पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है I

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों, मंत्रियों को पीएमएलए एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि इस एक्ट में इतने कड़े प्रावधान है कि गिरफ्तारी के बाद कम से कम 4-6 महीने तक गिरफ्तार व्यक्ति जेल में ही बंद रहेगा I चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले इस प्रकार से आम आदमी पार्टी के विधायकों की गिरफ्तारी केवल इसलिए की जा रही है, ताकि वह चुनाव के वक्त अपने विधानसभा से गायब रहे और चुनाव हार जाएं I सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार का मकसद केवल

इतना है, कि छल से, कपट से, धोखे से, कैसे भी करके आम आदमी पार्टी के विधायकों और नेताओं को जेल में डालना है I परंतु अब भाजपा के इस गुब्बारे की हवा निकलना शुरू हो गई है I उन्होंने कहा सबसे पहले उनकी इस गुब्बारे की हुआ तब निकली जब न्यायालय ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी I न्यायालय ने केंद्र सरकार और उनकी एजेंसी को कहा की 6 महीने में केस का ट्रायल पूरा हो जाना चाहिए था, परंतु 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आपका ट्रायल अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है I आप केवल यह चाहते हैं कि महीनो तक लोग जेल में बंद रहें I यही कारण है कि अब न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के लोगों को बिल देना शुरू कर दिया है I

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जो पत्रकार वहां मौजूद रहे होंगे उन्होंने देखा होगा, कि अमानतुल्लाह खान ओखला में तीन कमरे वाले एक फ्लैट में रहते हैं I वहां उनकी सास लेटी हुई है, जो कि कैंसर से पीड़ित है और दो दिन पहले ही उनका ऑपरेशन हुआ है I इस घर में उनकी बीवी है, बच्चे हैं I जानबूझकर बार-बार लगातार कभी ACB के द्वारा कभी सीबीआई के द्वारा तो कभी ईडी के द्वारा उनके घर में छापे मारे जा रहे हैं, घंटो घंटो तक घर में छानबीन चलती रहती है, घरवालों को परेशान किया जा रहा है और यह सब केवल और केवल घटिया राजनीति के चलते किया जा रहा है I उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म हो चुकी है कि कोर्ट द्वारा बार-बार फटकार लगाने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है I उदाहरण देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से ज़मानत मिला तो ट्रायल कोर्ट ने भी कहा और अब के. कविता को जब सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि यह क्या मजाक बना रखा है जांच एजेंसियों का, परंतु इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आ रही I

उन्होंने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार ने जांच एजेंसी का मजाक बना रखा है I मनमर्जी मुताबिक कार्रवाई की जा रही हैं I एक ही मामले में आरोपी अलग-अलग लोगों के साथ अलग-अलग तरह से व्यवहार किया जा रहा है I किसी को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, तो इस मामले में दूसरे व्यक्ति को अप्रूवर बना लिया जा रहा है, तो इसी मामले में तीसरे व्यक्ति को गवाह बना लिया जा रहा है और इसी मामले में चौथे व्यक्ति को जमानत दे दी जा रही है I अर्थात अपनी मर्जी के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है I उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है I इस देश की जनता ने अब तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता से विदा करना है । इस बार भाजपा की विदाई तय है ।

कोर्ट के समक्ष एक साथ पेश हुए केजरीवाल और सिसोदिया, अदालत ने ED को दिए अहम निर्देश

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में CM अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक साथ कोर्ट में पेश हुए। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने ईडी को मामले में आरोप पत्र के साथ दायर कुछ दस्तावेज भी आरोपितों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान आरोपितों की तरफ से विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को बताया गया कि ईडी द्वारा उन्हें पूरे दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराए गए हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्डिंग मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने ईडी को मामले में आरोप पत्र के साथ दायर कुछ दस्तावेज भी आरोपितों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान आरोपितों की तरफ से विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को सूचित किया गया कि ईडी द्वारा उन्हें पूरे दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराए गए हैं। इस पर अदालत ने एजेंसी को दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया, जबकि जमानत पर बाहर पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।

कोर्ट ने 6 सितंबर को सुनवाई की दी तारीख

उक्त निर्देश के साथ अदालत ने सुनवाई छह सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, हालांकि, सीबीआई मामले में केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण वह अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं।

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के उपराज्यपाल से हस्तक्षेप करने हेतू मुलाकात की

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज निवास में उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना से मुलाकात की और मौजूदा दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय के अवैध तरीके से पद पर बने रहने के संबंध में उपराज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया है कि शैली ओबेरॉय अप्रैल 2024 से बिना चुनाव कराए अपने पद पर हैं जबकि उनका कार्यकाल 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गया था।

कांग्रेस पार्टी जनप्रिय नेता राहुल गांधी और आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में दलितों, पिछड़ों और वंचितों के न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ती रही है और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव दिल्ली में दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हर संभव लड़ाई लडेंगे।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में उपराज्यपाल से मिलने वाले कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, पूर्व मेयर फरहाद सूरी, पूर्व पार्षद अभिषेक दत्त, निगम में कांग्रेस दल की नेता, निगम पार्षद नाजिया दानिश, निगम पार्षद हाजी जरीफ और निगम पार्षद शगुफ्ता चौधरी शामिल थी।

यादव ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के तीसरे वर्ष में, एक अनुसूचित जाति के सदस्य का मेयर बनना था, लेकिन सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं कराया। आप पार्टी द्वारा गैर संवैधानिक तरीके से एक ही व्यक्ति को मेयर पद पर जमाने के कारण अनुसूचित जाति के पार्षद को मेयर बनने से वंचित कर दिया है। शैली ओबेराय के लगातार मेयर पद पर बने रहने आप पार्टी में सहमति पिछड़े समुदायों के लोगों की जानबूझकर उपेक्षा करने को उजागर करता है।

देवेन्द्र यादव ने उपराज्यपाल के संज्ञान में लाया कि एमसीडी अधिनियम (धारा-35) के प्रावधानों के अनुसार, एमसीडी के तीसरे वर्ष में अप्रैल तक सदन के एक अनुसूचित जाति के सदस्य को मेयर के रूप में चुना जाना चाहिए। ''जबकि, निवर्तमान मेयर आज तक इस पद पर अवैध रूप से काबिज हैं'' और 31 मार्च, 2024 के बाद उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णय "अवैध और अदालत में चुनौती देने योग्य" है।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि भारतीय संविधान एससी/एसटी के अधिकारों को बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने बिना किसी देरी के अनुसूचित जाति समुदाय से एक नए मेयर की नियुक्ति में उपराज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग की और यह भी सुनिश्चित हो कि किसी भी दल द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए कानून के प्रावधानों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। यादव ने अनुरोध किया उपराज्यपाल महोदय को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि एससी/एसटी समुदाय के मेयर को पूरे एक साल का कार्यकाल मिले।

उन्होंने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उपराज्यपाल ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि दलित समुदाय के मेयर के चिंताजनक मसले पर मैं स्वयं गंभीर हूँ, आप निश्चित रहें। मैं दलित समुदाय के मेयर चुनाव के संबंध में जल्द कार्यवाही करने की कोशिश करुँगा।

भाजपा के मनगढ़ंत शराब घोटाले की कहानी का एक और ग़ुबारा आज फूट गया: मनीष सिसोदिया

सुषमा रानी

नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी ने 23 महीने बाद विजय नायर को मिली जमानत को सत्य की विजय बताया है। ''आप'' का कहना है कि धीरे-धीरे भाजपा की पूरी साज़िश धराशायी हो रही है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार ने हमारे नेताओं के खिलाफ साज़िश रची और उन्हें फ़र्ज़ी मामले लगाकर जेल में डाल दिया। लेकिन अब भाजपा की साज़िशों का लगातार खुलासा हो रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी और अब विजय नायर को जमानत दी है। अब मोदी सरकार के तमाम षड्यंत्रों को ध्वस्त करके जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे।

विजय नायर को जमानत मिलने पर ''आप'' के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि भाजपा के मनगढ़ंत शराब घोटाले की कहानी का एक और ग़ुबारा आज फूट गया। बिना सबूत, बिना कोई बरामदगी हुए विजय नायर को 23 महीने जेल में रखा। इनका मक़सद सिर्फ़ एक है कि अरविंद केजरीवाल को चुनावों में नहीं रोक सकते तो उनकी पूरी टीम और उन्हें ईडी-सीबीआई से गिरफ्तार करवाकर जेल में रखो। देर लग सकती है लेकिन अंत में जीत तो सत्य को ही होती है

''आप'' के राष्ट्रीय महासचिव संगठन एवं सांसद डॉ. संदीप पाठक ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा के मनगढ़ंत शराब घोटाले का एक और भंडाफोड़ हुआ है। विजय नायर को 23 महीने बिना सबूत जेल में क्यों रखा गया? सिर्फ केजरीवाल को रोकने के लिए?

''आप'' की वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड़यंत्र रचा और पार्टी के अनेकों नेताओं को जेल में डाला। लेकिन मनीष सिसोदिया और विजय नायर को ज़मानत मिलने के बाद यह साबित हो जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ एवं कैबिनेट मंत्री नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी मामले में पहले मनीष सिसोदिया को बेल मिली, फिर बीआरएस नेता के. कविता को बेल मिली और अब विजय नायर को भी सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। यह पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और केंद्र सरकार और उसकी ईडी-सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की बड़ी हार है, जो अब लगातार सुप्रीम कोर्ट और पूरे देश के सामने बेनकाब होते जा रहे हैं।

वहीं, "आप" के वरिष्ठ नेता जस्मीन शाह ने ट्वीट कर कहा कि आप के सभी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर खत्म करने की भाजपा की साजिश हर दिन बेनकाब हो रही है। पहले मनीष सिसोदिया को और अब विजय नायर को भी ज़मानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की शुरुआत में अनुचित देरी और अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार पर टिप्पणी की है।

खिली-खिली हो तुम

यू आधी उम्र में दिखी हो तुम।
फिर भी खिली-खिली हो तुम।
हम अब क्या करें शिकायत?
कभी तो नजरें करों इनायत।
हम भी तो तेरी राहों में खड़े हैं,
कहीं इधर-उधर नहीं पड़े हैं।
मैं जानता हूँ तकता हूँ तेरी राह,
कोई और न हो तेरी जिंदगी में
कभी न निकले किसी की आह।
किसी गलत-फहमी में ना रहना,
तुझमें हीरे-मोती तो नहीं जड़े हैं।
फिर भी राह में तेरी हम ही खड़े हैं।
यू आधी उम्र में दिखी हो तुम।
फिर भी खिली-खिली हो तुम।

ग़ज़ल : अहसांस आस-पास

ग़ज़ल : अहसांस आस-पास

किसी का होना इतना आसाँ नहीं।
जब ख़ुद की ही कोई पहचान नहीं।

तुम्हें तो डूब के करना होगा प्यार।
बिन इसके अपना जीना है बेकार।

चाहे हो जाए कितनी भी तकरार।
एक-दूजे पर कभी ना करना वार।

खूब खाओ कसमें निभाओं रसमें।
जमाने को करलों अपने ही बस में।

एक तू है जिसका मुझे अहसांस है।
ऐसा लगता है तू मेरे आस-पास है।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इंदौर (मध्यप्रदेश)
98260-25986

सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड दिल्ली आपातकालीन प्रतिक्रिया और सीपीआर प्रदर्शन पर विशेष सत्र

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। COVID-19 महामारी के बाद, कई व्यक्तियों में लगातार लक्षण दिखाई दे रहे हैं संभावित रूप से गंभीर हृदयाघात से होने वाली मौतों में वृद्धि हो सकती है, विशेषकर जनसंख्या युवाओं में ।

दिल्ली ब्रिगेड ने सर्वोदय (सह-शिक्षा) विद्यालय नंबर -3 सेक्टर -4 में एक विशेष सत्र का आयोजन किया, डॉ. अम्बेडकर नगर, नई दिल्ली -110062, 31 अगस्त 2024 को। सत्र का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और युवाओं और बच्चों में हृदय और श्वसन संबंधी आपात स्थितियों के बारे में समझ विकसित करना। इसमें सुरक्षा निर्देश, पहचान और चरण-दर-चरण कार्रवाइयां, और पूर्व-प्रदर्शन शामिल थे। अस्पताल सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन)।

इस सत्र में 59 शिक्षकों और 984 छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपना प्रदर्शन किया जीवन-रक्षक कौशल सीखने की प्रतिबद्धता। विद्यालय के प्राचार्य एवं अन्य प्रबंधन समिति सदस्य भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे का समर्थन करते हुए उपस्थित थे। सत्र, सुबह 9:00 बजे से आयोजित किया गया आगे बढ़ना और दो घंटे तक जारी रहना, दर्शकों के समर्पण का प्रमाण था। के अंत में सत्र में, प्रतिभागियों को प्रश्न पूछने और सही के साथ डमी पर अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया प्रभावी सीपीआर परिणामों के लिए तकनीकें। प्रतिभागियों ने इसे संभालने और स्थानांतरित करने के कौशल का भी अभ्यास किया हताहत. यह सत्र छात्रों की उत्साहपूर्ण बातचीत और प्रतिक्रियाओं के साथ संपन्न हुआ शिक्षकों ने आयोजन की सफलता में अपनी सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डाला।

दक्षिण पूर्व और दक्षिण जिलों की दिल्ली ब्रिगेड टीम। श्री पी डी वेरखिया, सहायक कमिश्नर, के नेतृत्व में श्री श्याम कुमार, कोर ऑफिसर, श्री दलीप कुमार डिविजनल कमांडर और श्री दिनेश यादव मैम्बर, सत्र का आयोजन एवं संचालन स्कूल समन्वयक शिक्षिका सुश्री पारुल नादर मैडम ने किया। स्कूल प्राधिकारियों ने इस सत्र की बहुत सराहना की, इसके मूल्यवान जीवन-रक्षक ज्ञान के कारण इसे और अधिक स्कूलों में विस्तारित करने की इच्छा व्यक्त की। यह सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शकों की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है, और दिल्ली ब्रिगेड है जीएनसीटी दिल्ली के सभी शैक्षणिक संस्थानों में इस पहल का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है आज का सन्दर्भ.

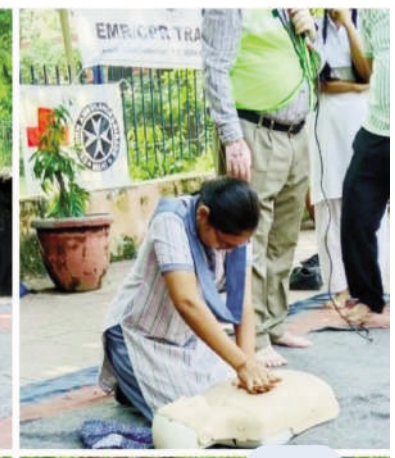

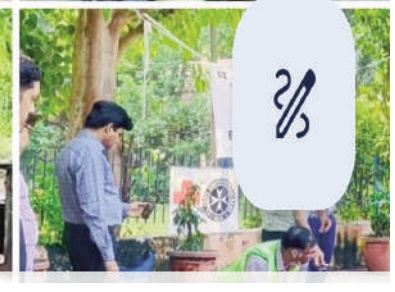

नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा का प्लान तैयार, एक हजार से ज्यादा CISF जवानों पर होगी जिम्मेदारी

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के हाथों में होगी। गृह मंत्रालय ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में 1047 जवान तैनात किए जाएंगे। एयरपोर्ट से अप्रैल 2025 के अंत तक यात्री सेवाएं शुरू होने की संभावना है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अप्रैल 2025 के अंत तक यात्री सेवाओं के शुरू होने की संभावना है।

ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के हाथ में होगी। सुरक्षा बल के 1047 जवान एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है। सुरक्षा बल के जवानों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था एयरपोर्ट की संचालक कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) करेगी। पिछले दिनों लखनऊ में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई संयुक्त समन्वय समिति की बैठक में एयरपोर्ट की सुरक्षा समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।

अगले वर्ष के अंत में शुरू होंगी फ्लाइट

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अप्रैल 2025 के अंत तक यात्री सेवाओं के शुरू होने की संभावना है। एयरपोर्ट उपकरणों की जांच के लिए सितंबर व अक्टूबर में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की जांच होगी। दिसंबर में वैलिडेशन और टेस्ट फ्लाइट के बाद एयरोड्रोम लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा।

विवाहित और अविवाहित जवानों के लिए अलग सुविधा

1334 हे. में बन रहे एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के 1047 जवानों को नियुक्त किया जाएगा, जो 24 घंटे एयरपोर्ट की निगरानी करेंगे। अविवाहित जवानों के लिए एयरपोर्ट परिसर में ट्रांजिट हॉस्टल बनाया जाएगा। विवाहित जवानों को आवासीय सुविधा के लिए परिसर से बाहर इंतजाम किए जाएंगे।

गृह मंत्रालय से मिली स्वीकृति

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती के लिए गृह मंत्रालय से स्वीकृति मिल चुकी है। एयरपोर्ट पर लगने वाले उपकरण साइट पर लगातार पहुंच रहे हैं। रडार आदि भी समय से एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे।

संयुक्त समन्वय समिति की बैठक में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, कस्टम, भारतीय मौसम विभाग आदि ने अपनी जरूरत से विकासकर्ता कंपनी के अधिकारियों को अवगत कराया है।

मुख्य सचिव ने एयरपोर्ट के कुशल संचालन के लिए विभागों की जरूरतों को नियमानुसार समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रनवे पर मार्किंग व लाइट का काम शेष है। टर्मिनल बिल्डिंग का काम जारी है।

फ्लैट खरीदने का मौका, GDA की 'पहले आओ-पहले पाओ' स्कीम लॉन्च

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने विभिन्न योजनाओं में खाली पड़े फ्लैट को बेचने के लिए 15 अगस्त को पहले आओ पहले पाओ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मोदीनगर में संजयपुरी योजना के तहत पहला विशेष शिविर लगाया गया जिसमें पहले दिन 15 फ्लैट बुक कराने वाले आवंटियों को आवंटन पत्र दिए गए। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए पढ़ें पूरी डिटेल।

गाजियाबाद।: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की विभिन्न योजनाओं में खाली पड़े फ्लैट को बेचने के लिए 15 अगस्त को पहले आओ पहले पाओ योजना लॉन्च की, जो अभी तक सफल रही है। रविवार को इसी क्रम में मोदीनगर में संजयपुरी योजना के तहत पहला विशेष शिविर लगाया गया, जिसमें पहले दिन 15 फ्लैट बुक कराने वाले आवंटियों को आवंटन पत्र दिए गए।

शिविर में योजना की जानकारी लेने के लिए भी 40 से अधिक लोग पहुंचे। जीडीए की पांच योजनाओं के फ्लैट की बिक्री नहीं हो सकी है। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऐसी संपत्तियों की कीमत नहीं बढ़ाई गई। इन संपत्तियों के लिए जीडीए ने पहले आओ पहले पाओ योजना शुरू की, जिसके तहत रविवार को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मोदीनगर के संजयपुरी योजना का विशेष शिविर लगाया।

खाली फ्लैट की जानकारी लेने पहुंचे करीब 300 लोग

शिविर में योजना के खाली फ्लैट के बारे में करीब 300 लोग जानकारी लेने पहुंचे। 15 लोगों ने फ्लैट खरीदे, जिन्हें जीडीए की ओर से आवंटन पत्र जारी किया गया। इन सभी ने संपत्ति की 10 प्रतिशत कीमत अदा की।

जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कुछ लोग फ्लैट खरीदने के लिए आए, लेकिन 10 प्रतिशत राशि जमा नहीं करा सके, जिन्हें जीडीए कार्यालय आकर 10 प्रतिशत रकम जमा कराने पर आवंटन पत्र जारी कर दिया जाएगा। स्कीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए अथॉरिटी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

लोन के लिए बैंक शाखाओं का लगा शिविर

प्राधिकरण की ओर से लगाए गए विशेष शिविर में कुछ बैंकों को भी आमंत्रित किया गया था। बैंक शाखाओं की ओर से स्टाल लगाकर लोगों को होम लोन के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक आफ इंडिया के स्टॉल लगे थे। इस दौरान लोगों को फ्लैट खरीदने पर मिलने वाली छूट के बारे में बताया गया।

जीडीए की इन योजनाओं में फ्लैट

जीडीए की पांच योजनाओं में फ्लैट नहीं बिक सके थे, जो खाली पड़े थे। इनमें मधुबन बापूधाम योजना के टू, थ्री, बीएचके के अलावा मिनी एमआइजी व एलआइजी फ्लैट हैं। चंद्रशिला योजना में टू बीएचके, इंद्रप्रस्थ योजना में वन, टू और थ्री बीएचके, कोयल एन्क्लेव योजना में वन व टू बीएचके, मोदीनगर के संजयपुरी योजना में ईडब्लूएस फ्लैट हैं।

जीडीए सचिव ने किया एसटीपी का निरीक्षण

जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने संजयपुरी में बने एसटीपी का निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे एसटीपी प्लांट का निरीक्षण करने के साथ ही सप्लाई चेन का भी निरीक्षण किया। उपस्थित आवंटियों की समस्याओं को सुनने के बाद उनका समाधान करने का भी आश्वासन दिया।

दिल्ली-NCR में नौकरी करने का सुनहरा मौका, 15 हजार पदों पर होगी भर्ती

अगर आप दिल्ली-एनसीआर में नौकरी करने की चाहत रखते हैं तो यह जानकारी आपके काम की है। दरअसल युवाओं को निजी कंपनियों में नौकरी दिलाने के लिए सितंबर में गाजियाबाद में रोजगार मेला लगेगा। इसमें सौ से अधिक कंपनियों में 15 हजार से अधिक रिक्त पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्त होगी। नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए प्रशासन द्वारा क्यूआर कोड जारी किया गया है।

गाजियाबाद। दिल्ली-एनसीआर की सौ से अधिक प्राइवेट कंपनियों में लगभग 15 हजार रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए जल्द ही गाजियाबाद में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।

रामलीला मैदान में लगेगा मेला

यह मेला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सितंबर महीने में गाजियाबाद आगमन पर घंटाघर स्थित रामलीला मैदान में लगाने की तैयारी है।

क्यूआर कोड से करें पंजीकरण

नौकरी के लिए अभ्यर्थियों को क्यूआर कोड के माध्यम से पंजीकरण कराना आवश्यक है। जिला प्रशासन ने क्यूआर कोड जारी कर दिया है।

सितंबर में मिलेगा मौका

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सितंबर माह के पहले सप्ताह में गाजियाबाद आ सकते हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, परियोजनाओं को सूचीबद्ध करने का कार्य किया जा रहा है।

बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी

गाजियाबाद आगमन पर मुख्यमंत्री सरकारी योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट, स्मार्टफोन वितरित करेंगे। चयनित पात्रों को लोन भी दिया जाएगा। इसके अलावा वृहद स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिससे बेरोजगारों को नौकरी मिल सके।

सौ से ज्यादा कंपनियों से किया गया संपर्क

इसके लिए सौ से अधिक कंपनियों से संपर्क किया गया है, जो रिक्त पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों को कंपनी में नियुक्ति देंगी।

कौन कर सकता है आवेदन?

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पीयूष राय ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति रोजगार मेले में प्रतिभाग कर नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसको क्यूआर कोड के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा।

गाजियाबाद में गरजा बुलडोजर, GDA ने मधुबन बापूधाम में 25 करोड़ रुपये की भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त

जीडीए की टीम ने मधुबन बापूधाम औद्योगिक पॉकेट में करीब 25 करोड़ रुपये कीमत की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। इसमें चारदीवारी कर फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। मधुबन-बापूधाम योजना के तहत ग्राम रसूलपुर याकूतपुर की भूमि करीब पांच हजार वर्ग मीटर औद्योगिक पॉकेट खसरा संख्या 42 की भूमि का मामला करीब डेढ़ दशक से न्यायालय की ओर से स्थगनादेश था।

गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की टीम ने पुलिस बल के साथ मधुबन बापूधाम औद्योगिक पॉकेट में करीब 25 करोड़ रुपये कीमत की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया, जिसमें चारदीवारी कर फैक्ट्री संचालित की जा रही थी।

मधुबन-बापूधाम योजना के तहत ग्राम रसूलपुर याकूतपुर की भूमि करीब पांच हजार वर्ग मीटर औद्योगिक पॉकेट खसरा संख्या 42 की भूमि का मामला करीब डेढ़ दशक से न्यायालय की ओर से स्थगनादेश था। स्थगनादेश समाप्त होने पर जीडीए की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया, जहां चारदीवारी कर फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था।

कब्जे वाली जमीन की कीमत 25 करोड़

प्राधिकरण के अधिकारियों ने अवैध कब्जे वाली इस भूमि की कीमत करीब 25 करोड़ रुपये बताई है। सोमवार को पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंची टीम ने प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर अवैध रूप से संचालित उक्त फैक्ट्री नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए भूमि को कब्जा मुक्त कराया।

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों से सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश

अजय कुमार

योगी सरकार ने सबसे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया। इसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और सदस्यों की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद उपचुनाव से पहले संगठन को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। पिछले ढाई वर्षों से लंबित पड़ी राजनैतिक नियुक्तियों का सिलसिला अब प्रदेश में आरंभ हो गया है। इन नियुक्तियों के माध्यम से योगी सरकार बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को विभिन्न निगम, आयोग, और बोर्ड में चेयरमैन और सदस्य के रूप में नियुक्त करके उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश में जुटी हुई है। यह रणनीति सरकार द्वारा सामाजिक समीकरणों को फिर से मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण योजना मानी जा रही है।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल 25 मार्च 2022 को आरंभ हुआ था। इसके बाद से ही बीजेपी कार्यकर्ता राजनैतिक नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि, सरकार और संगठन के बीच तनातनी के कारण आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और सदस्यों के नामों पर सहमति नहीं बन पा रही थी। हाल ही में लखनऊ में संघ, सरकार, और संगठन के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद राजनैतिक नियुक्तियों का यह सिलसिला शुरू किया गया है।

योगी सरकार ने सबसे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया। इसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और सदस्यों की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है। यह नियुक्तियां ढाई साल के अंतराल के बाद की गई हैं, जिससे प्रदेश के राजनैतिक समीकरणों को साधने की कवायद की जा रही है।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में सीतापुर के पूर्व सांसद राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। साथ ही मिर्जापुर के सोहन लाल श्रीमाली और रामपुर के सूर्य प्रकाश पाल को उपाध्यक्ष नामित किया गया है। इसके अलावा आयोग में 24 अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया है, जिनमें सत्येंद्र कुमार बारी, मेलाराम पवार, फुल बदन कुशवाहा, विनोद यादव, शिव मंगल बयार, अशोक सिंह, ऋचा राजपूत, चिरंजीव चौरसिया, रवींद्र मणि, आरडी सिंह, कुलदीप विश्वकर्मा, लक्ष्मण सिंह, विनोद सिंह, रामशंकर साहू, डॉ. मुरहू राजभर, घनश्याम चौहान, जनार्दन गुप्ता, बाबा बालक, रमेश कश्यप, प्रमोद सैनी, करुणा शंकर पटेल, महेंद्र सिंह राणा और राम कृष्ण सिंह पटेल शामिल हैं।

योगी सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन किया है। बाराबंकी के पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि गोरखपुर के पूर्व विधायक बेचन राम और सोनभद्र के जीत सिंह खरवार को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा आयोग में 17 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है, जिनमें हरेंद्र जाटव, महिपाल बाल्मीकि, संजय सिंह, दिनेश भारत, शिव नारायण सोनकर, नीरज गौतम, रमेश कुमार तूफानी, नरेंद्र सिंह खजूरी, तीजाराम, विनय राम, अनिता राम, रमेश चंद्र, मिठाई लाल, उमेश कठेरिया, अजय कोरी, जितेंद्र कुमार, और अनिता कमल शामिल हैं।

गोरखपुर यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर कीर्ति पांडेय को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में लंबित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। उपचुनाव से पहले योगी सरकार ने इन राजनैतिक नियुक्तियों के माध्यम से सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की कमान कुर्मी समुदाय के नेता को सौंपी है, जबकि अन्य ओबीसी जातियों को उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है, जिसमें पाल समाज को भी अहम स्थान दिया गया है। इसी तरह से आयोग में सदस्यों के रूप में अतिपिछड़ी जातियों को विशेष तवज्जो दी गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की कमान पासी समुदाय के नेता को सौंपी गई है, जबकि उपाध्यक्ष के पद पर खरवार समाज को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दलित समाज की अन्य जातियों के नेताओं को भी स्थान दिया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की कमान ब्राह्मण समाज से आने वाली कीर्ति पांडेय को दी गई है, जो सामाजिक समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम हैं, खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश की 80 में से सिर्फ 33 सीटें ही मिली हैं, जबकि 2019 में जीती हुई 29 सीटों का नुकसान हुआ है। प्रदेश में मिली इस हार ने बीजेपी को हिला कर रख दिया है, जिसके चलते उपचुनाव को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभालते हुए उपचुनाव वाली सीटों पर प्रचार के साथ-साथ संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू की है। इसके लिए उन्होंने नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाने का काम भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत राजनैतिक नियुक्तियों का यह सिलसिला शुरू हुआ है। पार्टी के बड़े नेताओं को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है, जबकि कार्यकर्ताओं को सत्ता में आने पर राजनैतिक नियुक्तियां मिलने की आस रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने अब नियुक्तियों का सिलसिला शुरू करके कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया है।

हालांकि, अभी भी कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां नहीं की गई हैं। राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष के अलावा पांच सदस्यों का कार्यकाल 2022 की शुरुआत में खत्म हो चुका है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, और 25 सदस्यों के पद भी खाली पड़े हैं। इसके अलावा प्रदेश के 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका, और 546 नगर पंचायतों में मनोनीत पार्षदों और सदस्यों की नियुक्तियां होनी हैं, जो 2022 से खाली हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पूर्व सैनिक कल्याण निगम, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश किन्नर विकास निगम, सिंधी अकादमी, पंजाबी अकादमी, और उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम में भी नियुक्तियां अभी लंबित हैं।

योगी सरकार में सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं, बल्कि सहयोगी दलों के नेता भी इन नियुक्तियों के लिए दावेदारी कर रहे हैं। अपना दल (एस), आरएलडी, सुभासपा, और निषाद पार्टी के नेता भी निगम, आयोग, और बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्य बनने की जुगत में हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले सपा, बसपा, और कांग्रेस से आए नेता भी इन नियुक्तियों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन नियुक्तियों के माध्यम से सत्ताधारी दल सूबे के सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास कर रहा है।

उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजां में इन नियुक्तियों का खासा असर दिखाई दे रहा है। उपचुनाव से पहले की जा रही ये नियुक्तियां स्पष्ट तौर पर चुनावी गणित को साधने के लिए हैं, जहां सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है।

– :सौजन्य :–

ईवी ड्राइव द फ्यूचर

EV Drive the Future

छत्तीसगढ़ की सड़कों पर 2 लाख से ज्यादा ईवी, सर्विसिंग सेंटर और स्पेयर पार्ट्स गायब, उपभोक्ता फोरम में दर्ज एक दर्जन शिकायतें

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले 3 सालों से छत्तीसगढ़ की सड़कों पर 2 लाख से ज्यादा दोपहिया, तिपहिया, कार और मालवाहक इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ रहे हैं। महंगे पेट्रोल-डीजल की कीमतों को देखते हुए इन्हें खरीदने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन मेंटेनेंस और सर्विसिंग की समस्या बनी हुई है साथ ही इन वाहनों के खराब होने पर इन्हें ठीक करने के लिए कोई मैकेनिक नहीं है।

वाहन में किसी तरह की खराबी या नुकसान होने पर उसे खींचकर शोरूम तक ले जाना मजबूरी बन गई है। इससे वाहन चालक भी परेशान हो रहे हैं। अगर किसी तरह वाहन लाया भी जाता है तो पार्ट्स की कमी और वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण कई दिनों तक शोरूम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके कारण कई लोग चाहकर भी ईवी खरीदने से बचते हैं।

खरीदने के बाद भी ज्यादातर लोग अपने वाहन का इस्तेमाल शहर के सीमित दायरे में ही करते हैं। रास्ते में वाहन के खराब होने का डर बना रहता है। इसके चलते 70 से 300 किमी की क्षमता होने के बावजूद लोग शहर से बाहर लंबी दूरी तय करने से बचते हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त 2022 में 5 साल के लिए ईवी नीति लागू की है। इसके तहत वाहन की कीमत का न्यूनतम 10 फीसदी और अधिकतम 1.50 लाख रुपए देना है। साथ ही वाहन को चार्ज करने के लिए सार्वजनिक स्थानों

पर चार्जिंग प्वाइंट शुरू किए जाने थे, लेकिन 2 साल बाद भी शहर के बाहरी जगहों पर चार्जिंग स्टेशन नहीं खोले जा सके हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में शहरी इलाकों में करीब 250 स्टेशन बनाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा रायपुर जिले में 30 जगहों पर चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है।

पिछले 5 सालों से छत्तीसगढ़ की सड़कों पर ईवी दौड़ रही है। कंपनी मोटर, बैटरी और चार्जर पर 3 साल की वारंटी और गारंटी देती है, लेकिन किसी अन्य तरह की खराबी होने पर डीलर के पास भागना पड़ता है। जब आप अपने वाहन को धुलवाने के लिए किसी निजी सर्विसिंग सेंटर जाते हैं, तो वे किसी तरह की दिक्कत होने पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। उनका कहना है कि प्रेशर पंप से वाहन धोते समय बैटरी या किट में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। टायर खराब होने, ब्रेक शू, लाइट लगाने या बड़ा पंचर होने पर वे टायर भी नहीं खोलते।

राडा अध्यक्ष विवेक गर्ग ने बताया कि ईवी को बढ़ावा देने के लिए कंपनियां अधिकृत डीलरों के माध्यम से माल उपलब्ध करा रही हैं। इसकी चेन बनाने के लिए धीरे-धीरे विस्तार किया जा रहा है। शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के मैकेनिकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि ईवी में कोई दिक्कत आने पर शोरूम और सर्विस सेंटर की दौड़ न लगानी पड़े।

ग्लोबल टाइम्स का 'हृदय परिवर्तन', टाटा मोटर्स का नाम लेकर जमकर की भारत की तारीफ

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चीन से ईवी बैटरी खरीदने का फैसला किया है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इस फैसले पर काफी खुशी जताई है। यह वही ग्लोबल टाइम्स है, जो भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। हालांकि, इस बार चीन के सरकारी मीडिया का हृदय परिवर्तन हुआ है और उसने टाटा मोटर्स के इस सौदे को दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि टाटा मोटर्स के इस कदम से हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे।

ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, "पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक वाहन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में हैं। ईवी जैसी हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले व्यवसाय नए व्यापार युद्ध का जरिया बन गए हैं। अमेरिका समेत कई देश चीन के खिलाफ कदम उठा रहे हैं और चीनी वाहनों के आयात पर अनुचित शुल्क लगा रहे हैं। वे इस आशंका को भी बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं कि पश्चिमी देशों में शुल्क के कारण चीनी इलेक्ट्रिक वाहन भारत जैसे बाजारों में डंप हो जाएंगे।₹ इसने आगे लिखा, ₹चीन दुनिया का अग्रणी ईवी प्लेयर है, इसलिए भारत के भीतर भी धारणाएँ हैं। कुछ लोग भारत से चीन की इलेक्ट्रिक वाहन प्रगति को पकड़ने और चीन के साथ व्यावहारिक सहयोग करने की मांग करते हैं, जबकि अन्य ईवी विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में चीन की जगह लेने की इच्छा

रखते हैं।"

ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा, ₹टाटा मोटर्स का नवीनतम कदम वैश्विक हरित उद्योग के विकास की वर्तमान स्थिति से संभव हुआ है। इस सौदे को चीन-भारत सहयोग की संभावना के संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है। जैसा कि अमेरिकी वाहन निर्माता फोर्ड ने हाल ही में कहा, ₹एक किफायती इलेक्ट्रिक वाहन एक किफायती बैटरी से शुरू होता है।₹ फोर्ड इस सिद्धांत को गहराई से समझता है। इसने पिछले साल मिशिगन में ईवी बैटरी फैक्ट्री बनाने के लिए चीनी बैटरी निर्माता CATL के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। हालांकि, अमेरिका में आंतरिक राजनीतिक कारकों के कारण, इस परियोजना को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है। स्पष्ट रूप से, टाटा मोटर्स फोर्ड की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है, खासकर कीमत-संवेदनशील भारतीय बाजार में।"

चीन की सरकारी मीडिया ने कहा ₹इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैश्विक स्तर पर हरित ऊर्जा उद्योग के राजनीतिकरण का जोखिम बढ़ रहा है। इसके बावजूद, टाटा मोटर्स ने राजनीतिक रूप से प्रेरित विकल्पों की परवाह किए बिना बाजार संचालित विकल्पों के माध्यम से अपनी लागत पर हरित उद्योग को विकसित करने का फैसला किया है।"

ग्लोबल टाइम्स ने आगे कहा, ₹भारत सरकार और व्यापार समुदाय दोनों को ईवी वाहनों से बहुत उम्मीदें हैं। भारत EV30@30 अभियान में शामिल है, जिसका लक्ष्य 2030 तक ईवी के लिए 30 प्रतिशत बिक्री हिस्सेदारी हासिल करना है। भारत सरकार ने घरेलू ईवी उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों को भी लागू किया है। हालांकि, मूल्य निर्धारण जैसे कारकों के कारण, भारत में वर्तमान ईवी वाहन की बिक्री उम्मीदों से कम रही है।"

ईवी मोबिलिटी सेवाओं का विस्तार, उत्तर प्रदेश में पैठ बनाने के लिए तैयार युलु बाइक्स

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक वाहन मोबिलिटी कंपनी युलु ने इलेक्ट्रिक वाहन डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करते हुए नोएडा में अपनी सेवाएँ शुरू की हैं। इस कदम के साथ युलु दिल्ली एनसीआर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर रही है। उत्तर प्रदेश की ईवी नीति के सहयोग से, यह फ्रैंचाइज़ ईज़ मॉडल के माध्यम से लखनऊ, वाराणसी और आगरा जैसे शहरों में अपनी सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रही है।

नोएडा में प्रवेश के साथ युलु अब देश भर के 11 शहरों में मौजूद होगा। नोएडा सातवां शहर है जहाँ बेंगलुरु, मुंबई, नवी मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम और हैदराबाद के बाद युलु की भौतिक उपस्थिति है। युलु अपने फ्रैंचाइज़ी मॉडल युलु बिजनेस पार्टनर के माध्यम से इंदौर, कोच्चि, तिरुनेलवेली और पांडिचेरी में भी काम करता है। युलु 2019 से दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय है।

ईवी-आधारित मोबिलिटी सॉल्यूशन युलु, आर्थिक परिदृश्य और त्वरित वाणिज्य और खाद्य

वितरण सेवाओं की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए नोएडा में विस्तार करने की योजना बना रहा है। नोएडा में कंपनी का प्रवेश उत्तर प्रदेश की ईवी विनिर्माण और मोबिलिटी नीति के अनुरूप है, जो अंतिम मील लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने में मदद करेगा। नोएडा में युलु का संचालन सेक्टर 63 में एक केंद्र से होगा। भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए केंद्र का विस्तार किया जाएगा। ई-बाइक के लिए बैटरी की आपूर्ति युमा एनर्जी द्वारा की जाएगी। नोएडा में बाइक केवल ई-कॉमर्स डिलीवरी के उद्देश्य से उपलब्ध कराई जाएंगी।

युलु ने स्विगी, ज़ोमैटो, जेप्टो और ब्लिंकिट जैसी प्रमुख डिलीवरी-आधारित कंपनियों के साथ साझेदारी की है। इससे उन लोगों को भी वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे जिनके पास अपना वाहन या ई-वाहन नहीं है। इससे कम से कम समय में सामान को वांछित गंतव्य तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों की थमी रफ्तार, किस बात से डरे निवेशक?

परिवहन विशेष न्यूज

ओला इलेक्ट्रिक के शेयर लिस्टिंग के बाद तूफानी रफ्तार से बढ़ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया। ओला अपने ऑल टाइम हाई लेवल से करीब 27 फीसदी गिर चुका है। इससे उन निवेशकों को काफी नुकसान हो रहा जिन्होंने इसे हाई पर खरीदा था। आइए जानते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में गिरावट क्यों हो रही है।

नई दिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में लिस्टिंग के बाद जबरदस्त तेजी देखी गई। इसकी 76 रुपये के अपर प्राइस बैंड पर फ्लैट लिस्टिंग हुई थी। फिर इसने टॉप गियर बनाया और एक ही हफ्ते में निवेशकों के पैसे डबल कर दिए। हालांकि, अब पिछले कुछ दिनों से ओला ने रिवर्स गियर लगा लिया है।

सोमवार को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 2.62 फीसदी गिरावट के साथ 114.90 रुपये के भाव पर बंद हुआ। यह लगातार चौथा दिन है, जब भाविश अग्रवाल की मालिकाना हक वाली कंपनी के शेयर लाल निशान में बंद हुए। 20 अगस्त को ओला ने 157.53 रुपये का अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तबसे यह करीब 27 फीसदी टूट चुका है।

Ola Electric के शेयर में गिरावट क्यों?

ओला इलेक्ट्रिक का घाटा लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट ओला के आईपीओ को काफी महंगा बता रहे थे। साथ ही, ओला इलेक्ट्रिक के मार्केट शेयर में भी गिरावट आई थी। यह जून तिमाही में 49 फीसदी थी, जो अगस्त के आखिर में घटकर 31 फीसदी रह गई। वहीं, ओला इलेक्ट्रिक की टीवीएस और बजाज ऑटो जैसी प्रतिद्वंद्वी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। इससे ओला के निवेशकों की चिंता भी बढ़ रही है और वे बिकवाली करके इससे बाहर निकल रहे हैं।

Ola Electric के तिमाही नतीजे कैसे रहे?

वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक के रेवेन्यू में उछाल देखने को मिला। हालांकि, इसका घाटा भी काफी बढ़ गया। जून तिमाही में कंपनी का शुद्ध घाटा बढ़कर 347 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल समान तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक को 267 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 32.3 फीसदी बढ़कर 1,644 करोड़ रुपये हो गया। यह एक साल पहले 1,243 करोड़ रुपये था।

ज़ोमैटो ने डिलीवरी पार्टनर्स के बीच इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ईवी बाज़ार का किया आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

2030 तक 100% डिलीवरी इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से करने की ज़ोमैटो की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में ज़ोमैटो ने सोमवार, 02 सितंबर को तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में अपना ईवी बाज़ार 2024 आयोजित किया। इस कार्यक्रम में डिलीवरी पार्टनर्स के लिए ईवी के लाभों पर प्रकाश डाला गया और उन्हें सही वाहन चुनने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया, जिसमें ईवी दोपहिया वाहन निर्माता, फ्लीट ऑपरेटर, चार्ज प्वाइंट प्रदाता और क्वांटम एनर्जी, काइनेटिक ग्रीन, बाउंस इनफिनिटी, लेक्ट्रिक्स, हीरो, टीवीएस, ओला, एम्पीयर, बैटफिट, ऑल्ट मोबिलिटी, बैटफिट, युलु, ज़िप, कदम मोबिलिटी और मूविंग अर्बन टेक्नोलॉजीज जैसे वित्तपोषण विशेषज्ञों जैसे प्रमुख उद्योग खिलाड़ियों की अंतर्दृष्टि शामिल थी।

दिल्ली सरकार के माननीय परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ईवी सेगमेंट में नवीनतम रुझानों और नवाचारों पर चर्चा करने के लिए ईवी इकोसिस्टम के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया। आरएमआई इंडिया की एमडी अक्षिमा घाटे और सीईईडब्ल्यू के निदेशक कार्तिक गणेशन ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई। ज़ोमैटो का ईवी मार्केटप्लेस दिल्ली सरकार के शहर को ईवी कैपिटल बनाने के लक्ष्य के अनुरूप है, जिसे दिल्ली ईवी पॉलिसी और 2023 मोटर व्हीकल एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम जैसी पहलों का समर्थन प्राप्त है।

इस कार्यक्रम में ज़ोमैटो ने अपना विशेष ईवी पोर्टल लॉन्च किया, जो ईवी डिप्लॉयर्स से तेज़ प्रतिक्रिया समय और त्वरित वाहन आवंटन को सक्षम करके परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक उपकरण है। यह ईवी डिप्लॉयर्स को इच्छुक डिलीवरी पार्टनर्स तक पहुँचने और उनके ईवी को किराए पर देने की अनुमति देता है, जबकि ज़ोमैटो-संबद्ध डिलीवरी पार्टनर(ओं) द्वारा उपयोग के लिए तैनात ईवी इन्वेंट्री को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करता है। इस कार्यक्रम में ईवी चलाने वाले शीर्ष डिलीवरी पार्टनर्स के लिए उच्च पुरस्कार और मान्यता भी देखी गई, जहाँ काइनेटिक ग्रीन और क्वांटम ने दो डिलीवरी पार्टनर्स को एक निःशुल्क ईवी प्रदान किया। ज़ोमैटो टीम ने अपने डिलीवरी नेटवर्क के लिए ईवी में सहज संक्रमण का समर्थन करने के लिए ईवी-केंद्रित फ़िल्में भी दिखाईं।

इस आयोजन पर टिप्पणी करते हुए ज़ोमैटो की मुख्य स्थिरता अधिकारी अंजलि रवि कुमार ने कहा, ₹ज़ोमैटो में हम 2030 तक 100% ईवी-आधारित डिलीवरी की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले ईवी मेलों और बाज़ारों की सफलता पर निर्माण करते हुए, जिसने वित्त वर्ष 23 में लगभग 5,000 डिलीवरी भागीदारों को पेट्रोल-आधारित बाइक से स्विच करने के लिए प्रभावित किया। ईवी बाज़ार अंतिम-मील डिलीवरी उत्सर्जन को कम करने के ज़ोमैटो के मिशन का समर्थन करता है। यह आयोजन यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि डिलीवरी पार्टनर ईवी के लाभों के बारे में अच्छी तरह से अवगत हों और उनके संक्रमण में उनका समर्थन किया जाए। उन्हें जानकारी हासिल करने के लिए एक मंच प्रदान करके हमारा लक्ष्य उनके बीच ईवी पैठ बढ़ाना और ईवी स्वामित्व के प्रति उनके इरादे को बदलना है।₹

दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत ने कहा, ₹दिल्ली सरकार पर्यावरण के प्रति जागरूक शहर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रही है। हम ईवी में बदलाव की पुरज़ोर वकालत करते हैं, उनके पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों को पहचानते हैं और ज़ोमैटो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियों द्वारा ईवी मार्केटप्लेस जैसी पहलों का समर्थन करते हैं, जिसका उद्देश्य गिग वर्कर्स के बीच जागरूकता बढ़ाना है।₹

1000 से ज़्यादा ज़ोमैटो और ब्लिंकिट ऑनबोर्ड डिलीवरी पार्टनर्स की भागीदारी के साथ, ईवी बाज़ार ने कई उपयोगी सत्रों का प्रदर्शन किया। मुख्य भाषण के बाद, ज़ोमैटो के बिजनेस हेड-ईवी अभिषेक द्विवेदी ने 2030 की समयसीमा से पहले टिकाऊ मिशन को पूरा करने के लिए ज़ोमैटो और ब्लिंकिट के डिलीवरी बेड़े में ईवी अपनाने को तेज़ करने के ज़ोमैटो के प्रयासों पर प्रकाश डाला। इस दिन ईवी के लाभों, एनबीएफसी द्वारा वित्तपोषण विकल्पों और ओईएम स्टॉल के साथ बातचीत पर प्रस्तुतियाँ शामिल थीं। कार्यक्रम का समापन डिलीवरी पार्टनर्स द्वारा टेस्ट ड्राइव में भाग लेने और ईवी सुविधाओं की खोज करने के साथ हुआ, जिससे उन्हें इन वाहनों के साथ व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में मदद मिली।

ज़ोमैटो 2022 से कार्बन-न्यूट्रल डिलीवरी की पेशकश कर रहा है और क्लाइमेट ग्रुप की ईवी100 पहल के सदस्य के रूप में 2030 तक 100% ईवी आधारित डिलीवरी की सुविधा देने का संकल्प लिया है। ज़ोमैटो का ईवी कार्यक्रम

ईवी आधारित डिलीवरी में इस बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए चार लीवर का उपयोग करता है: 90 से अधिक ईवी रेंटल कंपनियों और ओईएम और एक डिजिटल रेफरल टूल के साथ गठजोड़ के माध्यम से डिलीवरी भागीदारों के लिए किराए पर ईवी तक पहुँच में सुधार, ईवी आधारित लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं को शामिल करना, वित्तीय सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग के माध्यम से ईवी बाइक के स्वामित्व का समर्थन करना और अंत में, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन सक्रियण के माध्यम से डिलीवरी के लिए ईवी के उपयोग के विभिन्न मॉडलों और लाभों के बारे में डिलीवरी पार्टनर की जागरूकता बढ़ाना।

काइनेटिक ग्रीन के सीईओ रितेश मंत्री ने कहा कि काइनेटिक ग्रीन को डिलीवरी पार्टनर्स के लिए ईवी को और अधिक सुलभ बनाने के लिए ज़ोमैटो के साथ साझेदारी करने पर गर्व है। काइनेटिक ब्रांड को भारतीय 2-व्हीलर सवारों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है और इस ईवी बाज़ार जैसे आयोजनों के माध्यम से, हमारा लक्ष्य अपने ग्रीन स्कूटर रेंज और विशेष रूप से हमारे नए ई-लूना के लाभों को प्रदर्शित करना है, जो अपने स्टाइलिश और मजबूत चेसिस, सामान ले जाने के लिए पर्याप्त जगह और सुविधा और किसी भी इलाके के लिए पर्याप्त ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ एक आदर्श समाधान के रूप में डिलीवरी पार्टनर्स की ज़रूरतों को पूरा करता है। हम इस साझेदारी को आगे बढ़ाने और लाखों लोगों तक ग्रीन मोबिलिटी लाने के लिए तत्पर हैं।

फ़तेह आलम, डिलीवरी पार्टनर, ज़ोमैटो, ₹मैं पिछले दिसंबर से ईवी चला रहा हूँ और यह ईंधन की बचत और रखरखाव के मामले में बहुत फ़ायदेमंद रहा है। यह प्रदूषण मुक्त भी है। मुझे खुशी है कि ज़ोमैटो ने ईवी सुपरस्टार के रूप में मेरी पसंद और प्रयासों को मान्यता दी है।"

चीन से घटाना होगा व्यापार घाटा

डा. जयंती लाल भंडारी

निश्चित रूप से दुनिया के बाजार में चीन का दबदबा तोड़ने के परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय, अमरीका और अन्य कई देश चीन से आयात के बढ़ते खतरों के मद्देनजर चीनी आयातों पर असाधारण आयात प्रतिबंध लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विगत 12 जून को यूरोपीय आयोग ने चीन में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 48 फीसदी तक आयात शुल्क लगाना सुनिश्चित किया है।

इस बात को भी समझना होगा कि चीन से व्यापारिक असंतुलन की गंभीर चुनौती के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। चीन के साथ व्यापार असंतुलन के लिए सीधे तौर पर देश का उद्योग-कारोबार और देश की कंपनियां भी जिम्मेदार हैं, जिनके द्वारा कलपुर्जे सहित संसाधनों के विभिन्न स्रोत और मध्यस्थ विकसित करने में अपनी प्रभावी भूमिका नहीं निभाई गई है। साथ ही देश की बड़ी कंपनियों को शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ना होगा'

हाल ही में थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष 2024 के पहले छह महीनों यानी जनवरी से जून 2024 के दौरान भारत का चीन के साथ अब तक का सर्वाधिक व्यापार घाटा दर्ज किया गया है, जिसका आकार 41.6 अरब डॉलर है। इस अवधि में चीन से आयात बढ़कर 50.1 अरब डॉलर हो गया। जबकि चीन को सिर्फ 8.5 अरब डॉलर का निर्यात किया गया। यदि हम पिछले संपूर्ण वित्त वर्ष 2023-24 में चीन के साथ भारत के व्यापार को देखें तो पाते हैं कि चीन से आयात 101.75 अरब डॉलर हुआ था। जबकि चीन को निर्यात 16.66 अरब डॉलर रहा तथा चीन के साथ व्यापार घाटा 85.09 अरब डॉलर रहा है। निश्चित रूप से चीन के साथ बढ़ता हुआ व्यापार घाटा देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक प्रोत्साहन आधारित उत्पादन (पीएलआई) के तहत एपीआई का उत्पादन बढ़ाकर इसके चीन से बढ़े पैमाने पर होने वाले आयात में कमी की जा रही है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक चीन को खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के रणनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इन दिनों भारत-चीन के व्यापार से संबंधित प्रकाशित हो रही विभिन्न वैश्विक आर्थिक व वित्तीय संगठनों की रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि इस समय भारत के पास चीन से आयात घटाने और वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़ाए जाने की संभावनाएं हैं।

इन संभावनाओं को साकार किए जाने के चार प्रमुख आधार हैं। एक, चीन से निकलते बड़े उद्योगों, बड़ी कंपनियों और निवेश के भारत की मु_ियों में आने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। इससे भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा। दो, चीन प्लस वन रणनीति के तहत भारत दुनिया के सक्षम व भरोसेमंद देश के रूप में निर्यात बढ़ा सकता है। साथ ही अमरीका सहित यूरोपीय व कई विकसित देश चीन से आयात घटाने के लिए चीनी उत्पादों पर जिस तरह असाधारण आयात प्रतिबंध लगा रहे हैं, उससे इन देशों में भारत के उत्पादों का निर्यात बढने की नई संभावनाएं हैं। तीन, देश से चीन को कृषि पदार्थों और खाद्य प्रसंस्करण निर्यात में तेज वृद्धि की जा सकती है। चार, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किए गए प्रावधानों से भारत के आयात घटने व निर्यात बढने की संभावनाएं हैं। उल्लेखनीय है कि वैश्विक वित्तीय कंपनी नोमूरा ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन से ग्लोबल कंपनियां बाहर निकल रही हैं जिसका बड़ा फायदा भारत को मिलता दिख रहा है।

नोमूरा के द्वारा चाईना प्लस वन स्ट्रेटजी पॉलिसी को लेकर 130 फर्मों के साथ सर्वे किया गया है। कहा गया है कि खासतौर से भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, सेमीकंडक्टर (एसेंबलिंग, टेस्टिंग), एनर्जी (सोलर) के अलावा फार्मास्युटिकल्स सेक्टर की कंपनियों का भारत में हर संभव सुविधा देकर स्वागत किया जाना होगा। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि जी-20 की नई शक्ति से सुसज्जित भारत नए वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश की भूमिका में उभरकर सामने आया है और चीन को आर्थिक टक्कर देने की स्थिति में है। ऐसे में भारत अधिक रणनीतिक प्रयासों से भारतीय बाजार में उद्योग-कारोबार, निर्यात और निवेश के अधिक मौकों को मु_ियों में ले सकता है।

निश्चित रूप से दुनिया के बाजार में चीन का दबदबा तोडने के परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय, अमरीका और अन्य कई देश चीन से आयात के बढ़ते खतरों के मद्देनजर चीनी आयातों पर असाधारण आयात प्रतिबंध लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विगत 12 जून को यूरोपीय आयोग ने चीन में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 48 फीसदी तक आयात शुल्क लगाना सुनिश्चित किया है। पिछले कई वर्षों से यूरोपीय देशों की चीन से आयात पर शुल्क की दरें 10 फीसदी तक ही सीमित रही हैं। ऐसे में विभिन्न देशों के द्वारा चीन से आयात होने वाले अनेक उत्पादों पर लगातार बढ़ता शुल्क चीन के आयातों को हतोत्साहित करने की एक अहम पहल है, ऐसे में इन देशों में भारत से निर्यातों की संभावनाएं बड़ी है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि चीन को कृषि निर्यात बढ़ाए जाने की प्रचुर संभावनाएं है, देश से कृषि उत्पाद बढ़ाने के साथ कृषि निर्यात बढ़ाने की रणनीतिक पहल की जा रही है। वित्तमंत्री सीतारमण के द्वारा पेश किया गया वर्ष 2024-25 का बजट भी उद्योगों को समृद्ध करने का बजट है। इस बजट के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करते हुए आयात घटाने व निर्यात बढ़ाने के अभूतपूर्व प्रावधान किए गए हैं। इससे चीन का भारतीय बाजारों पर जो दबदबा बना हुआ है, उसमें भी कमी आते हुए दिखाई दे सकती है। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर देश से निर्यात और रोजगार सृजन दोनों में अहम योगदान देता है और इसके प्रोत्साहन के लिए इस बजट में खास ख्याल रखा गया है। वित्तमंत्री ने बजट में देश के 100 शहरों में प्लग एंड प्ले वाले औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है। केंद्र, राज्य और निजी सेक्टर की आपसी सहभागिता से प्लग एंड प्ले सुविधा वाले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे।

उद्यमी को ऐसे औद्योगिक पार्क में जाकर सिर्फ उत्पादन शुरू करना होता है। नए बजट के प्रावधानों के तहत 100 शहरों में प्लग एंड प्ले वाले सुविधा वाले औद्योगिक क्लस्टर या पार्क के विकसित होने से कम से कम 100 प्रकार के आइटम का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता है। वर्ष 2024-25 के बजट में वित्तमंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को निर्यात बढ़ाने के मद्देनजर सशक्त बनाया है। साथ ही इस सेक्टर के आयात में कमी के मद्देनजर प्रावधान किए गए है। निस्संदेह अब एक बार फिर से देश के करोड़ों लोगों को चीनी उत्पादों की जगह स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के नए संकल्प के साथ आगे बढना होगा। इस बात को भी समझना होगा कि चीन से व्यापारिक असंतुलन की गंभीर चुनौती के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। चीन के साथ व्यापार असंतुलन के लिए सीधे तौर पर देश का उद्योग-कारोबार और देश की कंपनियां भी जिम्मेदार हैं, जिनके द्वारा कलपुर्जे सहित संसाधनों के विभिन्न स्रोत और मध्यस्थ विकसित करने में अपनी प्रभावी भूमिका नहीं निभाई गई है। साथ ही देश की बड़ी कंपनियों को शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढना होगा।

इस बात पर भी गंभीरतापूर्वक ध्यान देना होगा कि जिस तरह हाल ही में यूरोपीय यूनियन और अन्य विकसित देशों के द्वारा चीन से आयात नियंत्रित करने के लिए गैर टैरिफ अवरोध के साथ अन्य आयात प्रतिबंधों को असाधारण रूप से बढ़ाया गया है, उसी तरह भारत के द्वारा संरक्षणवाद के तरीके अपनाते हुए चीन से तेजी से बढ़ रहे आयात और चीन के साथ बढ़ते हुए व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढना होगा।

ज्ञान

भीड़ कम करने के लिए

भीड़ कम करने की वजह हिमाचल के शहरी आवरण को फिर से लिखने की जरूरत सरीखी है। वीरभद्र सिंह के बाद यह पैगाम सुक्खू सरकार ने दिया है कि राजधानी से कुछ कार्यालय जिला मुख्यालयों को रुखसत किए जाएंगे। शांता कुमार सरकार ने बिजली महकमे के कई कार्यालय सुंदरनगर भेजे थे, तो वीरभद्र सिंह ने नार्थ, साउथ व सेंट्रल जोन बनाकर विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय और कुछ मुख्यालय स्थानांतरित किए थे। प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालयों का एक और जोन बनाकर हमीरपुर में इनकी तादाद बढ़ाई थी। बेशक शिमला में राजधानी के हिस्से बंटे और इन्हीं से निकला था निचले क्षेत्रों में मुख्यमंत्री का शीतकालीन प्रवास, तपोवन में शीतकालीन सत्र और धर्मशाला में शीतकालीन राजधानी का सफर। एक बार फिर शिमला की बाहों से भीड़ का बोझ निकाला जाएगा। यह संभव है अगर नगर की डगर पर आसमानों का युद्ध न हो, वरना सत्ता की मंजिलें सियासी भीड़ बन जाती हैं। देखना यह भी होगा कि शिमला से उठा कर भीड़ किस शहर की संपत्ति बनने के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। मसलन कृषि विश्वविद्यालय अगर पालमपुर में है, तो कृषि विभाग का निदेशालय वहां हो सकता है। इसी तरह मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी के साथ चिकित्सा निदेशालय व सोलन विश्वविद्यालय के कारण बागबानी का निदेशालय वहां शिफ्ट किए जा सकते हैं। स्कूली बोर्ड शिक्षा व खेल नगरी के रूप में धर्मशाला में शिक्षा, खेल, युवा सेवाएं, भाषा एवं कला-संस्कृति तथा पर्यटन जैसे विभाग भेजे जा सकते हैं। बीबीएन क्षेत्र को प्रदेश की आर्थिक राजधानी का दर्जा देने के लिए उद्योग, प्रदूषण, वित्त निगम तथा औद्योगिक विकास निगम के कार्यालयों का औचित्य वहां बढ़ जाता है। इसके साथ बैंकिंग क्षेत्र की राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय बीबीएन में शिफ्ट कर देने चाहिए। शिमला के उच्च न्यायालय का सर्किट बैंच धर्मशाला में खोलने की दशकों पुरानी मांग को पूरा करने की दिशा में भी सरकार को अहम भूमिका निभानी चाहिए। शिमला को मिला राजधानी का दर्जा इसकी ऐतिहासिक विरासत का परचम बुलंद करता है, इसलिए यहां 'राज्य राजधानी क्षेत्र' की तर्ज पर विकास करना होगा। वर्षों से लंबित वाकनाघाट परियोजना को अब शिमला के भविष्य के अनुरूप विकसित करना चाहिए। बेशक शिमला को भीड़ से मुक्त कराने का एक तरीका इजाद हो रहा है, लेकिन भीड़ में मंदिर परिसरों, पर्यटक स्थलों, बढ़ते यातायात की मजबूरियों और परिवहन के दबाव को घटाने की जरूरत है। प्रदेश में दो-तीन शहरों के मध्य कर्मचारी नगर बसा कर नए कार्यालयों के लिए स्थान बनाया जा सकता है। शिमला से कार्यालय शिफ्ट कर देने से राज्य की भीड़ कम नहीं होगी। हमें याद रखना चाहिए कि पांच करोड़ पर्यटक आगमन का इंतजार पुनः शिमला के रिज, सडक़ों और पर्यटक स्थलों को खचाखच भर देगा। ऐसे में हर शहर की भूमिका में निखार लाने से पहले उसके मूल आचरण का वर्गीकरण करते हुए ही विभागों के कार्यालय शिफ्ट करने होंगे। उदाहरण के लिए सोलन का विस्तार अपने आगोश में शिमला, किन्नौर व सिरमौर के लोगों का बेतरतीब आसरा बन रहा है। भुंतर से मनाली तक लाहुल-स्पीति व पांगी के लोगों का ठिकाना बनता जा रहा है, तो जरूरत शहरीकरण के हर मुद्दे को संबोधित करने की भी है।

राजनीतिक साये में जर्जर होती अर्थव्यवस्था

हिमाचल कांग्रेस जानती थी कि केंद्र में विपक्ष की सरकार है, जहां से आर्थिक सहायता की उम्मीद नहीं की जा सकती, फिर भी ओपीएस अर्थात पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना चुनावी मुद्दा तय कर लिया, बेशक कांग्रेस ने हर राज्य में इसे चुनावी मुद्दा बनाया हो, परंतु हिमाचल जैसे छोटे से पहाड़ी राज्य में आय का कोई बड़ा साधन न होने के कारण ओपीएस को बहाल कर अब सरकार आर्थिक संकट में आ चुकी है

कहने को तो राजनीति समाज सेवा का जरिया है, लेकिन वास्तव में नेताओं ने राजनीति को महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति का रास्ता मान लिया है। व्यावहारिकता का परिक्षण किए वगैर सत्तासीन होने के लिए एक से बढक़र एक अनेक वायदे अपने चुनावी घोषणा पत्र में कर दिए जाते हैं। बाद में जब वायदे पूरे करने में सरकार नाकाम रहती है, तो तरह-तरह के बहाने बनाए जाते हैं। वैसे भी जयराम सरकार के समय में हुए पुलिस भर्ती पेपर लीक कांड, अवैध शराब कांड और ट्रैजेडी, अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग, कमजोर गवर्नेंस और व्यापक भ्रष्टाचार एवं भाजपा के भीतर पनपती आपसी फूट के बाद हिमाचल की जनता बदलाव के मूड में थी, परंतु शायद कांग्रेस कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए भारी भरकम आत्मघाती वायदों का पिटारा खोल बैठी। कांग्रेस एक अच्छी गवर्नेंस के साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन के वायदे के साथ चुनाव लड़ती, तो भी सत्तासीन हो जाती। हिमाचल कांग्रेस जानती थी कि केंद्र में विपक्ष की सरकार है, जहां से आर्थिक सहायता की उम्मीद नहीं की जा सकती, फिर भी ओपीएस अर्थात पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना चुनावी मुद्दा तय कर लिया, बेशक कांग्रेस ने हर राज्य में इसे चुनावी मुद्दा बनाया हो, परंतु हिमाचल जैसे छोटे से पहाड़ी राज्य में आय का कोई बड़ा साधन न होने के कारण ओपीएस को बहाल कर अब सरकार आर्थिक संकट में आ चुकी है। दूसरी तरफ सरकार की बदकिस्मती से लगातार दो वर्षों से प्रदेश में आ रही प्राकृतिक आपदाओं ने सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री का प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए दो माह के लिए स्वयं के, मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों के वेतन भत्ते बंद कर विधायकों से वेतन भत्ते न लेने का आग्रह करना सरकार की बेबसी को झलकाता है, इस सबके बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा असंवैधानिक पदों पर बिठाए गए सलाहकारों, ओएसडी निगमों और बोर्डों के अध्यक्षों की लंबी चौड़ी फौज से वेतन भत्ते छोडऩे का कोई आग्रह, अब तक सामने नहीं आया है।

आय न हो तो खर्चों पर लगाम लगानी पड़ती है और आय के साधनों पर ध्यान कैंद्रित करना पड़ता है, परंतु सरकार ने पुराने ढर्रे पर चल रही सरकारी व्यवस्था को बदलने के बजाय पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त कर लगाने, पूर्व सरकार द्वारा खोले गए अनावश्यक के साथ-साथ जरूरी दफ्तरों, विभागों, स्कूलों को भी बंद कर दिया। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के बजाय भ्रष्टाचार पर सरकार की पकड़ को ढीला कर दिया। भ्रष्ट अधिकारियों को महत्त्वपूर्ण पदों पर बिठाया गया या उन्हें सेवा-विस्तार दे दिया गया। माननीयों के वेतन भत्तों में कटौती न कर, विधायकों मंत्रियों की दोहरी-तिहरी पेंशन व्यवस्था पर भी कभी विचार ही नहीं किया गया। कांग्रेस पर परिवारवाद के लिए अंगुली उठती रही है, आज भी ऐसे कई विधायक हैं जिनके पिता, सदन के सदस्य रह चुके हैं, ऐसे परिवारों में तीन चार पेंशन आ रही है क्या यह सही है? जब प्रदेश का युवा बेरोजगारी की आग में जल रहा हो और सरकार का खजाना खाली हो तो, प्रदेश के हर विधायक को एक डाटा आपरेटर रखने का अधिकार प्राप्त है, जिसकी एवज में उन्हें पंद्रह हजार रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त भत्ता मिलता है। हिमाचल विधानसभा हर विधायक को यह भत्ता प्रदान कर रही है, जबकि आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष देव भट्टाचार्य द्वारा जून माह में जुटाई गई जानकारी के मुताबिक हिमाचल सचिवालय के पास विधानसभा द्वारा माननीयों को दिए जा रहे इस प्रकार के किसी भत्ते का रिकार्ड ही नहीं है कि कितने विधायकों ने डाटा आपरेटर रखे हैं न ही सचिवालय में डाटा आपरेटर के संबंध में कोई बिल जमा है। ऐसी अव्यवस्था के बीच न केवल माननीयों की मौज हो रही है, बल्कि बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा भी हो रहा है। माननीयों को पंद्रह हजार रुपए प्रति माह टेलीफोन भत्ता भी दिया जाता है, लैंडलाइन टेलीफोन के जमाने से चली आ रही इस प्रथा का आज के युग में क्या औचित्य रह जाता है, मुख्यमंत्री जी सोचिएगा जरूर। अपने चुनावी हल्फनामे में करोड़ों, अरबों की संपत्ति डिक्लेयर करने वाले एवं आय के विभिन्न स्रोत बताने वाले माननीयों के वेतन के अलावा भत्तों पर अगर नजर दौड़ाएं, तो वो इस प्रकार हैं:प्रतिपूरक भत्ता 5 हजार रुपए प्रतिमाह, विधानसभा क्षेत्र भत्ता 90 हजार, टेलीफोन भत्ता 15 हजार रुपए, कार्यालय भत्ता 30 हजार और डाटा ऑपरेटर भत्ता के लिए 15 हजार रुपए मिलते हैं।

यह आम जनता का पैसा है। ये भत्ते उन्हें तब तक मिलते हैं,जब तक वह विधायक रहते हैं। इसके अलावा विधानसभा सत्र की बैठक के लिए प्रति बैठक 1800 रुपए रोजाना दिया जाता है। वहीं, ट्रैवलिंग अलाउंस, फ्री यात्रा सुविधा, आवासीय सुविधा समेत कई तरह की सुविधाएं विधायकों को दी जाती हैं, जो समाज सेवा के नाम पर जनता के दुख दर्द को बांटने के लिए चुने जाते हैं। ऐसी व्यवस्था के बीच व्यवस्था परिवर्तन का नारा दे कर मात्र दो महीनों के वेतन भत्ते उपवास से क्या प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी? प्रदेश के खनिजों से होने वाली आय को विभाग के अधिकारियों एवं माफियाओं की सांठगांठ से चूना लगाया जा रहा है। खनिजों के अत्याधिक दोहन में नेताओं की और सरकार के नजदीकी व्यक्तियों की भूमिका से भी इंकार नहीं किया जा सकता। पिछली सरकार के समय सुलह विधानसभा क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ वहां के पूर्व विधायक ने लंबे समय तक मोर्चा खोले रखा, परंतु उनकी अहमियत को ही दबा दिया गया है। उन्हें जातीय समीकरणों के आधार पर पार्टी टिकट से ही वंचित कर दिया गया। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जो न केवल प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन रहा है, बल्कि सरकारी खजाने पर भारी चपत लगा रहा है। यह कैसा व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है मुख्यमंत्री जी बताएं! पिछली सरकार द्वारा बनाई गईं गौशालाएं ढहने के कगार तक पहुंच चुकी हैं। गाय के नाम पर भारी उपकर लेने और 100 करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने के बावजूद प्रति गाय 1200 रुपए महीना गाय के भरण-पोषण के लिए दिया जाना कितना व्यावहारिक है?

नीलम सूद

शव संवाद-59

पौंछे का दर्द और बुद्धिजीवी का मर्ज लगभग एक जैसा है। दोनों सदियों से घिसट रहे हैं या इन्हें घसीटा जा रहा है। पौंछा निचुड़ रहा है, तो बुद्धिजीवी को निचोड़ा जा रहा है। देश जिस गति से सफाई पसंद होता जा रहा है, बुद्धिजीवी उससे भी तेज गति से पौंछा होता जा रहा है। अंबानी के बेटे की शादी जिस तरह चलती रही, उससे कई लोग भी पौंछा बन गए। दरअसल इस शादी ने पूरे विश्व को बता दिया कि हिंदुस्तान में किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था क्यों न हो, ऐसे समारोह के आयोजन में कई विदेशियों तक की हैसियत को पौंछा बना सकता है। खैर बुद्धिजीवी अंबानी की शादी में मीन मेख निकालने समारोह स्थल पर पहुंच चुका था। वहां की चमक का राज लिए एक पौंछा बाहर ही बुद्धिजीवी को मिल गया। वह खाया पीया पौंछा था। वह कई पौंछों का बाप और पौंछा नस्ल का एकमात्र अमीर पौंछा था। उसे हाथ में पकड़ते ही बुद्धिजीवी को डर लग रहा था कि कहीं पौंछा मैला न हो जाए। बुद्धिजीवी ने बड़े अदब से पौंछे को नमस्कार किया और जितना शिष्टाचार सरकार और अंबानी परिवार के बीच देखा था, उससे कहीं अधिक उसने पौंछे को दे दिया। बदले में पौंछा जैसे ही मुस्कराया, उसके बदन से शादी के सारे व्यंजनों की महक बाहर निकल आई। बुद्धिजीवी के लिए यह गौरव की बात थी। वैसे तो गरीब से गरीब पौंछा भी सफाई के काम में थिरकता है, लेकिन अंबानी के घर का पौंछा विदेशी धुनों पर नाच रहा था।

इसका बस चलता तो अमरीका जाकर इस बार भी कह देता कि 'आएगा तो ट्रंप ही।' बुद्धिजीवी मुस्कराते पौंछे को देखकर खुद पर तरस खाने लगा। पल भर तो उसे लगा कि कहीं लोगों ने उसके लिए अंबानी के पौंछे को मुस्कराते देख लिया, तो उसे ही विश्व गुरु न समझ लें। खैर जैसे ही वे दोनों सहज हुए, तो पौंछे ने स्वयं आगे बढक़र बुद्धिजीवी को गले लगा लिया, जैसे वे हरिद्वार महाकुंभ के बिछुड़े दो भाई हों। पौंछा उसे अंबानी के घर की शादी का आंखों देखा हाल सुनाने लगा, तो बुद्धिजीवी देश की तरक्की पर भरोसा करने लगा। पौंछे ने बताया, 'मेरी बिरादरी फटी पुरानी, प्राचीन सभ्यता में जीने वाली रही है, लेकिन अचानक एक दिन अंबानी की शादी ने मुझे क्या से क्या बना दिया। मैं बाकायदा कंपीटीशन से इस स्थान पर पहुंचा हुआ हूं, वरना वहां तो सारे विश्व के लोग पौंछा बनने को तैयार थे। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय व निवास तक के पौंछे चाहते थे कि वे अंबानी के घर की अमानत बनें, लेकिन मेरा भाग्य सरकारी ठेके की तरह था, लिहाजा अवसर मिल गया। मैंने अंबानी के घर में बिना टांगों का विश्व देखा है। बड़े लोग बिना टांगों के हमारी तरह के पौंछों की वजह से साफ खड़े होते हैं।'

पौंछा अपनी सफलता की बातें बताते हुए भी निराश दिख रहा था। उसे डर था कि कहीं पौंछे का पेटेंट करवा कर अंबानी उसके वजूद को भी अपनी बौद्धिक संपदा न बना दे। वह बुद्धिजीवी से अनुनय करने लगा कि वह उसे कहीं दूर गंगा में बहा दे। पौंछे का साहस-सामथ्र्य जवाब दे चुका था। बुद्धिजीवी ने उसे कंधे पर रखा और हरिद्वार पहुंच गया। आश्चर्य यह कि जब पंडों को पता चला कि अंबानी का कोई पौंछा आया है, तो वे उसकी मुक्ति के लिए बुद्धिजीवी से खासे पैसों की मांग करने लगे। यह सोच कर कि अंबानी के पौंछे को सीधे स्वर्ग में जगह मिले, बुद्धिजीवी ने न केवल उसके लिए दान-पुण्य किया, बल्कि मृतकों के पंजीकरण रजिस्टर में उसका नाम अपने मरे हुए बुजुर्गों के नाम के साथ लिखवा दिया। आखिर यह भारत में ही तो संभव है कि हम अपने पितृ दोष से इस हद तक मुक्त हो सकते हैं। -क्रमशः

निर्मल असो

85 दिनों में ढाई लाख करोड़ के इन्फ्रा प्रोजेक्टों को मंजूरी, कैसी है मोदी 3.0 की रफ्तार?

परिवहन विशेष न्यूज

आम चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि चार जून को नतीजे आने के बाद अफसरों के लिए इतना काम आने वाला है कि उन्हें जरा भी फुर्सत नहीं मिलेगी। पहले सौ दिनों में ही सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को धार देने के साथ ही न्यू इकोनॉमी से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ले चुकी है। पिछले एक सप्ताह में तीसरी बार कैबिनेट की बैठक तेज रफ्तार काम की बानगी है।

नई दिल्ली। कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के साथ ही हाईवे, मेट्रो, पोर्ट, एयरपोर्ट, पर्यावरण, गरीबों और मध्य वर्ग के लिए घर, शोध और अनुसंधान यानी दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले लगभग हर क्षेत्र में अहम फैसलों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साझा सरकार होने के बावजूद तीसरी पारी की वैसी ही शुरुआत की है, जैसा उन्होंने वादा किया था।

सोमवार को किसानों के लिए लगभग 14000 करोड़ की सात योजनाओं के एलान के साथ केंद्र सरकार ने विकास के साथ राजनीतिक संदेश देने का सिलसिला भी जारी रखा। नौ जून को शपथ लेने के बाद से अब तक 85 दिनों के भीतर मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ढाई लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

विकास पर फोकस के साथ ही शुरुआती सौ दिनों में ही सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना लाकर विपक्षी दलों और विशेष रूप से कांग्रेस से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी छीन लिया। इस पेंशन योजना से 23 लाख केंद्रीय कर्मियों को लाभ होगा। मोदी सरकार की तीसरी पारी के पहले सौ दिनों की एक और विशेषता तथा राजनीतिक मोर्चे पर सक्रियता एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के संदर्भ में यह निर्णय लेने की रही कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा।

मोदी सरकार की रफ्तार तेज क्यों?

आम चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि चार जून को नतीजे आने के बाद अफसरों के लिए इतना काम आने वाला है कि उन्हें जरा भी फुर्सत नहीं मिलेगी। पहले सौ दिनों में ही सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई धार देने के साथ ही न्यू इकोनमी से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ले चुकी है। पिछले एक सप्ताह में तीसरी बार कैबिनेट की बैठक और इसी अवधि में पूरी मंत्रिपरिषद के साथ चर्चा तेज रफ्तार काम की बानगी है। नवीनतम एलान गुजरात में एक और सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना का है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि काम करने की तेज रफ्तार बनी हुई है और यह बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को मंजूरी देने के सिलसिले से प्रमाणित होती है। सरकार गठन के बाद लगभग तीन महीने में कैबिनेट की 15 बैठकें हो चुकी हैं। सरकार ने तीसरी पारी की शुरुआत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों और गांवों में तीन करोड़ नए घर बनाने के एलान से की थी। इसके तहत केवल गांवों में अगले पांच सालों में दो करोड़ घर बनाए जाने हैं, जिन पर 2.30 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। बाकी एक करोड़ घर शहरों में बनेंगे।

किसानों को भी एमएसपी का फायदा

किसानों के लिए एमएसपी वाली सभी फसलों पर सौ रुपये से लेकर 550 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। हाईवे और एक्सप्रेस वे निर्माण के साथ तेज रफ्तार विकास के अपने एजेंडे को जारी रखते हुए पहले सौ दिनों ही 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के आठ कारिडोर को मंजूरी दी गई है, जिनमें अयोध्या में एक बाईपास और कानपुर में रिंग रोड भी शामिल है।

शुरुआती सौ दिनों ही वाराणसी एयरपोर्ट के विकास पर 2869 करोड़ रुपये खर्च करने को भी मंजूरी दी गई है। मेट्रो की कई अहम परियोजनाओं को सरकार की अनुमति मिली है, जिनमें बेंगलुरु में दो नए कारिडोर, थाणे में इंटीग्रल मेट्रो रेल और पुणे में मेट्रो परियोजना का विस्तार शामिल है। इन पर तीस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे।

अगस्त में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर में नरमी रही

परिवहन विशेष न्यूज

पीएमआई के तहत 50 से ऊपर होने का मतलब उत्पादन गतिविधियों में विस्तार जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट को दर्शाता है। एचएसबीसी के मुख्य अर्थशास्त्री (भारत) प्रांजुल भंडारी ने कहा कि अगस्त में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में विस्तार जारी रहा है। हालांकि विस्तार की गति थोड़ी धीमी रही। नए ठेकों और उत्पादन में मुख्य रुझान देखने को मिला।

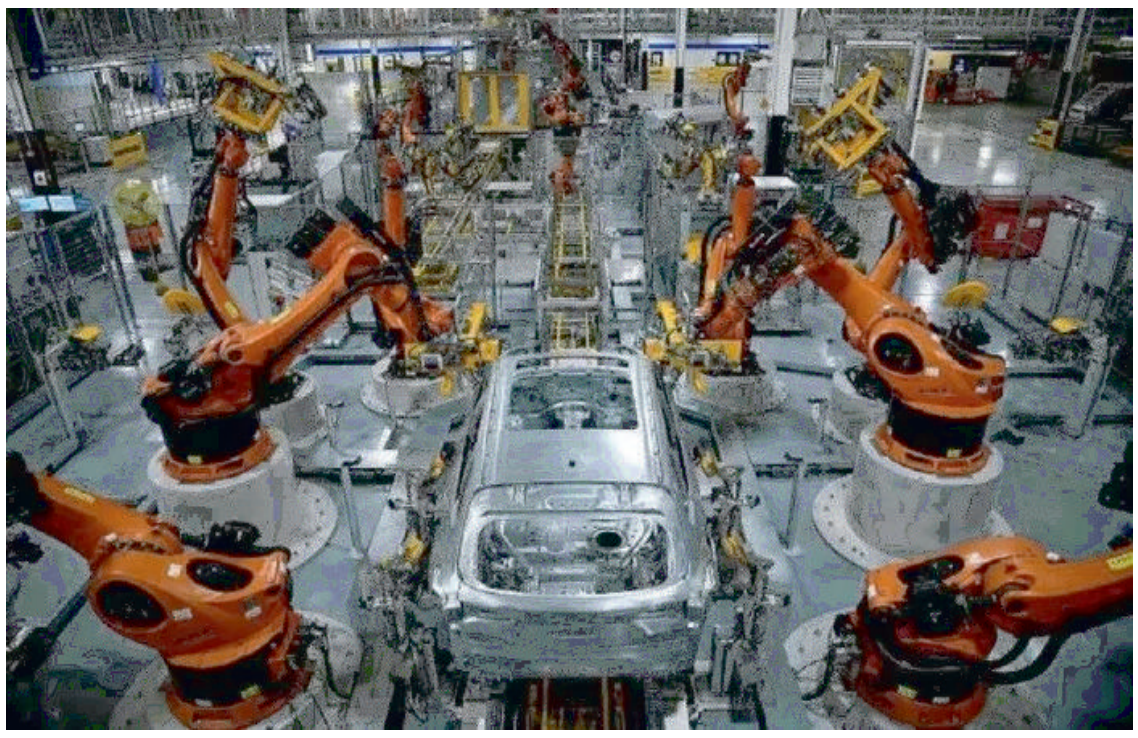

नई दिल्ली। अगस्त के दौरान मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर में नरमी रही है। इसका कारण उत्पादन व बिक्री में जनवरी के बाद से सबसे कम बढ़ोतरी और प्रतिस्पर्धा दबाव रहा है। एचएसबीसी इंडिया के मासिक सर्वे में यह बात कही गई है। सर्वे के अनुसार, अगस्त में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) 57.5 रहा है जो इसी वर्ष जुलाई में 58.1 था। पीएमआई के तहत 50 से ऊपर होने का मतलब उत्पादन गतिविधियों में विस्तार, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट को दर्शाता है। एचएसबीसी के मुख्य अर्थशास्त्री (भारत) प्रांजुल भंडारी ने कहा कि अगस्त में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में विस्तार जारी रहा है। हालांकि, विस्तार की गति थोड़ी धीमी रही। नए ठेकों और उत्पादन में मुख्य रुझान देखने को मिला। इस दौरान कुछ कारोबारियों ने मंदी के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा को एक मुख्य वजह बताया है।

सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में नए कारोबार में तेजी से वृद्धि हुई, लेकिन विस्तार की गति सात महीने के निचले स्तर पर आ गई। इसी तरह, नए निर्यात आर्डर कैलेंडर वर्ष 2024 की शुरुआत के बाद से सबसे कम गति से बढ़े। कीमतों के मोर्चे पर, वस्तु उत्पादकों को अगस्त के दौरान लागत दबाव में कमी से लाभ हुआ है।

कारोबारी आत्मविश्वास में कमी आई है जो अप्रैल 2023 के बाद से सबसे कम निचले स्तर पर है। भंडारी ने कहा कि प्रतिस्पर्धी दबावों और महंगाई संबंधी चिंताओं के कारण अगस्त में वर्ष के लिए कारोबारी दृष्टिकोण में थोड़ी नरमी आई है।

2000 के नोट पर RBI का अपडेट, 97.96 प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आए

अब केवल 7261 करोड़ रुपये के नोट प्रचलन या लोगों के पास रह गए हैं। आरबीआई ने 19 मई 2023 को दो हजार रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय 3 .56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के दो हजार रुपये के नोट प्रचलन में थे। 7 अक्टूबर 2023 तक इन नोटों को सभी बैंकों की शाखाओं में जमा करने या बदलने की सुविधा थी।

नई दिल्ली। आरबीआई ने सोमवार को बताया कि प्रचलन से बाहर हो चुके दो हजार रुपये के 97.96 प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। अब केवल 7,261 करोड़ रुपये के नोट प्रचलन या लोगों के पास रह गए हैं। आरबीआई ने 19 मई 2023 को दो हजार रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के दो हजार रुपये के नोट प्रचलन में थे। आरबीआई ने सात अक्टूबर 2023 तक इन नोटों को सभी बैंकों की शाखाओं में जमा करने या बदलने की सुविधा थी। इस समय आरबीआई के सभी 19 क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिये लोग दो हजार रुपये के नोटों को अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं। 2000 रुपये के नोटों को जमा करने और/या बदलने की सुविधा देश की सभी बैंक शाखाओं में 7 अक्टूबर, 2023 तक उपलब्ध थी। आम लोग देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से 2000 रुपये के बैंक नोट किसी भी RBI निर्गम कार्यालय में अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए भेज रहे हैं।

किसानों के आने वाले हैं अच्छे दिन, कृषि क्षेत्र पर 14 हजार करोड़ खर्च करेगी मोदी सरकार

पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कृषि क्षेत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें 7 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन पर कुल 14000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पिछले कुछ समय से जीडीपी में कृषि का योगदान घट रहा था। लेकिन मोदी सरकार की हालिया पहल से कृषि क्षेत्र और किसानों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र पर काफी फोकस कर रही है। इस सेक्टर की जीडीपी और रोजगार पैदा करने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को कृषि क्षेत्र से जुड़ी सात बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी। इन पर सरकार करीब 14,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इनमें से 2,817 करोड़ रुपये का डिजिटल कृषि मिशन के लिए दिए जाएंगे। वहीं, फसल विज्ञान पर 3,979 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन फैसलों को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा और प्रबंधन को बेहतर करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये के प्रोग्राम को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि पशुधन के स्थायी स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये के प्लान को मंजूरी दी गई है। सरकार का फोकस बागवानी पर भी है। उसने बागवानी के सतत विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की एक बड़ी योजना मंजूरी दी है। साथ ही, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने पर 1,202 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित योजना पर 1,115 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सभी सातों योजनाओं के लिए कुल 13,960 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।

जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ को सेबी ने 'होल्ड' किया, तीन अन्य को दिखाई हरी झंडी

परिवहन विशेष न्यूज

कई तरह के कारोबार करने वाले जेएसडब्ल्यू ग्रुप की जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने 16 अगस्त को सेबी के पास आईपीओ को लेकर कागज जमा की थी। डीआरएचपी के मुताबिक प्रस्तावित आईपीओ में 2000 करोड़ रुपये का नया इश्यू और 2000 करोड़ रुपये की ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) शामिल है। लेकिन सेबी ने अभी के लिए जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ को होल्ड कर दिया है।

नई दिल्ली। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जेएसडब्ल्यू सीमेंट (JSW Cement) के प्रस्तावित 4,000 करोड़ रुपये के IPO को होल्ड पर डाल दिया है। हालांकि, सेबी ने यह नहीं बताया कि उसने जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ को होल्ड क्यों किया है।

कई तरह के कारोबार करने वाले जेएसडब्ल्यू ग्रुप की जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने 16 अगस्त को सेबी के पास आईपीओ को लेकर कागज जमा की थी। डीआरएचपी के मुताबिक, प्रस्तावित आईपीओ में 2,000 करोड़ रुपये का नया इश्यू और 2,000 करोड़ रुपये की ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) शामिल है।

तीन कंपनियों के आईपीओ को मंजूरी

सेबी ने तीन कंपनियों के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। इनमें व्हीकल फाइनेंसिंग और कर्मशियल लोन देने वाली एसके फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस की माइक्रो-फाइनेंस यूनिट बेलस्टार माइक्रोफाइनेंस और ट्रांसरेल लाइटिंग शामिल हैं। सेबी के एक अपडेट से यह जानकारी मिली।

सेबी ने तीनों कंपनियों को 30 अगस्त को आईपीओ लाने की मंजूरी दी है। एसके फाइनेंस का प्रस्तावित आईपीओ 500 करोड़ रुपये के नए शेयरों और प्रमोटर एवं निवेशकों के पास मौजूद 1,700 करोड़ रुपये तक के शेयरों की बिक्री पेशकश का मिलाजुला रूप है।

बेलस्टार माइक्रोफाइनेंस का आईपीओ 1,300 करोड़ रुपये का है। वहीं, ट्रांसरेल लाइटिंग के आईपीओ में 450 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू और प्रमोटर द्वारा एक करोड़ से अधिक इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश शामिल है। इन कंपनियों के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे।

सेबी का प्लानः SIP में 250 रुपये से शुरू कर सकेंगे निवेश, IPO भी कई भाषाओं में होगा उपलब्ध

सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच ने कहा कि सेबी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) दस्तावेजों को कई भाषाओं में उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। इससे भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने और निवेशक जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। धवी पुरी बुच का कहना है कि निवेशक जल्द ही 250 रुपये प्रति माह से एसआईपी में निवेश कर सकेंगे। मार्केट रेगुलेटर इस दिशा में जरूरी कदम उठा रहा है।

नई दिल्ली। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। खासकर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये आम निवेशकों को काफी पसंद आ रही हैं। लेकिन, अभी एसआईपी की न्यूनतम किस्त एक बड़ा मसला है। ज्यादा फंड हाउस 1 हजार या 5 सौ रुपये वाली एसआईपी स्कीमें चलाते हैं। सिर्फ चंद फंड ही हैं, जो 100 रुपये महीना वाली स्कीम ऑफर करते हैं।

लेकिन, अब कम एसआईपी किस्त चाहने वाले निवेशकों को अधिक विकल्प मिल सकता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच का कहना है कि निवेशक जल्द ही 250 रुपये प्रति माह से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) में निवेश कर सकेंगे।

सेबी चीफ ने क्या कहा?

उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम में बुच ने कहा कि हम 250 रुपये मासिक किस्त वाली एसआईपी को हकीकत बनाने की राह पर हैं। अभी अधिकांश फंड हाउस न्यूनतम एक हजार या पांच सौ रुपये प्रति माह के निवेश वाली एसआइपी संचालित करते हैं। कुछ ही फंड हाउस 100 रुपये प्रति माह के निवेश वाली एसआइपी का विकल्प देते हैं।

बुच ने कहा कि सेबी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) दस्तावेजों को कई भाषाओं में उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। इससे भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने और निवेशक जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

रीट पर टिप्पणी से इन्कार

हितों के टकराव की बात कहते हुए बुच ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट) पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया और कहा कि ऐसी इकाइयों के सरलीकरण के नियम मौजूद हैं। अमेरिकी की शार्ट-सेलर फर्म ने हाल में आरोप लगाया था कि रीट से जुड़े हालिया संशोधनों से एक विशिष्ट वित्तीय समूह को लाभ पहुंचा है। हालांकि, सेबी ने इन आरोपों से इन्कार किया था।

कार्यक्रम में बुच ने कहा कि एक्सचेंज में एक ही फाइलिंग बहुत जल्द वास्तविकता बन जाएगी और किसी सूचीबद्ध कंपनी की ओर से एक शेयर बाजार में दी गई जानकारी स्वतः ही दूसरे एक्सचेंज पर 'अपलोड' हो जाएगी।

आईपीओ लिस्टिंग के एक ही हफ्ते में 54 फीसदी शेयर बेच देते हैं निवेशक, क्या है वजह?

सेबी ने आईपीओ में निवेश करने वालों लोगों के मनोविज्ञान को समझने के लिए एक स्टडी की है। इससे कई दिलचस्प चीजें पता चलती हैं। जैसे कि अगर किसी आईपीओ की लिस्टिंग घाटे में हुई है तो लोग उसे ज्यादा वक्त तक होल्ड करके रखते हैं मुनाफे में आने का इंतजार करते हैं। वहीं पॉजिटिव लिस्टिंग गेन वाली आईपीओ स्टॉक को बेचने के लिए एक किस्म की जल्दबाजी दिखती है।

नई दिल्ली। पिछले दिनों एक गुमनाम कंपनी का आईपीओ आया था, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल। इसके दिल्ली में सिर्फ दो बाइक शोरूम हैं, जिनमें 8 लोग काम करते हैं। लेकिन, इसके आईपीओ को 418 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया। कंपनी को आईपीओ से सिर्फ 12 करोड़ जुटाने थे, मगर बोली मिली 4800 करोड़ रुपये की। इससे पता चलता है कि निवेशकों में आईपीओ को लेकर कितना क्रेज है। कई निवेशकों तो एक से अधिक डीमैट अकाउंट से आईपीओ के लिए बिडिंग करते हैं।

लेकिन, दिलचस्प बात यह है कि आईपीओ के लिए मारामारी करने वाले ज्यादातार रिटेल इन्वेस्टर्स आवंटन के एक हफ्ते के भीतर ही 54 फीसदी शेयर बेच देते हैं। यह बात मार्केट रेगुलेटर सेबी की एक स्टडी से पता चली है। स्टडी में एक मजबूत डिस्पोजिशन इफेक्ट पाया गया यानी वित्तीय लाभ कमाने वाली संपत्तियों को समय से पहले बेचने की प्रवृत्ति। सेबी की स्टडी निवेशकों के मनोविज्ञान के बारे में कई दिलचस्प बातें बताती है। जैसे कि अगर किसी आईपीओ की लिस्टिंग घाटे में हुई है, तो लोग उसे ज्यादा वक्त तक होल्ड करके रखते हैं, मुनाफे में आने का इंतजार करते हैं। वहीं, पॉजिटिव लिस्टिंग गेन वाली आईपीओ स्टॉक को बेचने के लिए उनके अंदर एक किस्म की जल्दबाजी दिखती है। पिछले कुछ समय से आईपीओ में इन्वेस्टर्स की भागीदारी काफी ज्यादा बढ़ी है। इससे कई कम वैल्यू वाले आईपीओ भी हद से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जा रहे हैं, जैसा कि रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल के मामले में हुआ। सेबी ने मेन-बोर्ड आईपीओ में निवेशकों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए गहन अध्ययन किया।

लोग बोले - "हमारे देश में ऊंच-नीच, भेद-भाव और जातिवाद आज़ केंसर से भी बड़ी घातक बीमारी बन गया है"

- अब आरक्षण विरोधी सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू समाज को आपस में लड़ाने की रच रहे साजिश,
- 'फूट डालो और राज करो' की राजनीति कर रहे हैं आरक्षण विरोध,
- न्यायहित में भागवतजी, मोदीजी और योगीजी जातिवाद की आढ़ में दलितों के साथ हो रही गुंडागर्दी को बंद कराएं

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत को आजाद हुये 78वर्ष हो गये हैं। भारत विश्वगुरु बनने को अग्रसर हैं, लेकिन आज़ देश का कोई कोना ऐसा बाकी नहीं हैं जहाँ असहाय कमजोर दलितों आदिवासी और पिछड़ों पर अत्याचार ना हो रहें हों। हैवानियत ऐसी की सुन कर आप की रूह कांप जाए। जबकि कुछ लोग अब सोशल मीडिया के माध्यम से आरक्षण के नाम पर हिंदू समाज को आपस में लड़ाने की साजिश रच रहे हैं।

इस गंभीर विषय पर जब हमारे संवाददाता संजय साग़र सिंह ने लोगों से उनकी राय जानी तो उन्होंने बताया कि, आज़ पूरी दुनियां कट्टरपंथी आर्तकियों के अत्याचारों के खिलाफ़ लड़ रही हैं, लेकिन हमारे भारत देश में कुछ आरक्षण विरोधी अपने ही हिन्दू दलित भाइयों से आरक्षण के नाम पर लड़ रहे हैं। आज़ पूरे देश में ऐसा कोई पुलिस थाना, चौकी और कोट कचहरी बाकी नहीं बची जहां दलितों पर अत्याचारों की शिकायते ना आती हों। जबकि दस साल से डॉ मोहन भागवत जी, देश के प्रधानमंत्री मोदीजी और सीएम योगीजी रात दिन जातिवाद में बांटे हिन्दुओं को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि, कोई ट्रेनी डॉक्टर से रेप कर हत्या कर रहा हैं। कोई बच्चियों को ग़लत काम करके पेड़ से लटका देता हैं। तो कोई मासूम बच्चों को मटके से पानी पीने पर पीट पीट कर मार देता हैं, तो कोई खाने से उठा देता हैं, तो कोई पेशाब पीला देता हैं, और कोई थूक जटवाता हैं, तो कोई पानी नहीं पीने देता। तो कोई घोड़ी नहीं चढ़ने देता, तो कोई मूंछ नहीं रखने देता, तो कोई जमीन पर कब्जा कर लेता हैं। तो कोई नीची जाति देख बैरहमी से मारपीट कर देता हैं। तो कोई मंदिर में जाने नहीं देता। जातिवाद से ग्रसित मनसिकता के लोग हर जगह अपनी मनमानी कर रहे हैं।असहाय दलितों, आदिवासी और पिछड़ों पर इतने अत्याचार होने के बाद भी अत्याचारी हैवान आरक्षण को कमजोर गरीबो से छीनना चाहते हैं और सोशल मीडिया पर तर्क देते फिरते हैं कि आरक्षण भीख हैं। तो फिर क्या मोदीजी जो 10 % सुदामा आरक्षण इनको दे रहें हैं और ये ले रहें। तो इस भीख को तो इनको हरगिज़ नहीं लेना चाहिए। क्युकी ये इनको भी पंगू बना देगा। फिर भी इन अत्याचारियों को दिनरात सोते जागते कमजोरों का आरक्षण खटकता हैं, लेकिन दलितों पर हर जगह हो रहें अत्याचार इन अत्याचारियों को नहीं दिखते हैं।

उन्होंने कहा, दुनियां देख रही हैं कि दलित के साथ हो रहे अत्याचारों पर भारत में भागवत जी, मोदीजी और योगीजी कोई बोलने को तैयार नहीं हैं, सब चुप्पी साधे हैं। क्या इस देश में दलित, आदिवासी और पिछड़ों को सम्मान एवं स्वाभिमान से जीने का अधिकार नहीं हैं ? पुरे संसार में क्या कोई ऐसा देश हैं जहाँ पर नीची जाति के नाम पर किसको पेशाब पिलाया गया या थूक कर चटवाया गया हैं बताये..? लेकिन भारत में इनके अत्याचारों की लिस्ट बहुत लम्बी हैं। वहीं, दलितों को मिल रहे आरक्षण से परेशान लोग सोशल मीडिया के माध्यमो से लोगों को आरक्षण के विरोध में भड़का कर अत्याचारों को ओर बढ़ावा दे रहें हैं। और जातिवाद से ग्रसित मनसिकता के लोग अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रहित में और न्यायहित में हमारी आप से अपील हैं कि जातिवाद की आढ़ में दलितों के साथ हो रही गुंडागर्दी को बंद कराएं और इन अत्याचारियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। क्युकी हमारे देश में जातिवाद, ऊंच-नीच, भेद-भाव केंसर से भी बड़ी घातक बीमारी हैं। ज़बतक इसका पक्का इलाज नहीं होगा तबतक आपका का सब का साथ, सब का विकास का सपना साकार नहीं हो सकता। क्या भागवत जी, मोदीजी और योगीजी भारत में वो दिन आएगा जब सभी हिंदू एकजुट होकर कहेंगे - 'हम सब एक हैं और एकजुट हैं ?

उन्होंने आगे कहा, पूर्व में जिस तरह से विदेशी आक्रांताओं ने हिंदू समाज में फूट डालने का षड्यंत्र रचा था। आजकल उसी तरह से देश में दलित विरोधी आरक्षण के नाम पर हिंदू समाज को आपस में लड़ाने की साजिश रच रहे हैं। अब जातिवादी जहरीली सोच इन चंद हिन्दू एकता विरोधियों को बीमार नहीं बहुत बीमार बना रही हैं और यही बीमार मानसिकता अपनों पर ही अमानवीय अत्याचार और गुंडागर्दी के रूप में पूरी दुनियां के सामने उभर कर आने लगी हैं। अब इन आरक्षण विरोधियों को इस बात की चिंता है कि अमानवीय अत्याचार सहते हुए भी दलित समाज के युवा गरीबी में भी अपनी कड़ी मेहनत, बुद्धि और विवेक के बल पर कैसे इतनी तरक्की प्राप्त कर ले रहे हैं। इसलिए वह सोशल मीडिया पर अपना गैंग बनाकर आरक्षण को विवादित करने की साजिश सुबह - शाम रचते रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर लगातार हो रही आरक्षण विरोधी पोस्टों से देखने में आया हैं कि आरक्षण विरोध के चलते कुछ दलित विरोधी देश विरोधी ताकतों को गले से लगाकर देश में हिन्दू एकता को तोड़कर अराजकता, गुंडागर्दी और दंगों की आग में झोंकने का कार्य कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सेक्यलुर यानि हिन्दू विरोधी शक्तियों को आरक्षण अच्छा नहीं लगता हैं। जिन लोगों ने दलित समाज की नौकरियों में डकैती डाली, जिन लोगों ने दलित युवाओं का रोजगार छीना और जिन लोगों देश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया और जातिवाद को बढ़ाया, आज़ वो चंद आरक्षण विरोध लोग समाज में 'फूट डालो और राज करो' की राजनीति कर रहे हैं। जो दलित समाज अपनों के हर तरह के अत्याचार चुप चाप सहते हुए भी सबसे अधिक देश सेवा करता रहा लेकिन आरक्षण विरोधोयों ने दलितों को कभी अपना नहीं समझा बल्कि आरक्षण विरोध लोगों ने जाति के नाम पर हिन्दुओं को भड़काकर समाज को आपस में लड़ाने का कार्य किया। इसके लिए आरक्षण विरोधियों ने स्मार्ट फोन और सोशल मीडिया को हथियार बनाया है। इसके माध्यम से झूठे वक्तव्य को फैला रहे हैं।

उन्होंने कहा, ये अत्याचारी लोग दलितों के आरक्षण पर तो सुबह शाम आंसू बहाते रहते हैं और सोशल मीडिया पर भी लगातार कैपेंन चलाते रहते हैं किंतु बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर मौन हो जाते हैं। इन दलित, संबिधान, और आरक्षण विरोधियो की सभी समीक्षाएं व चर्चायें पूरी तरह से आरक्षण विरोध पर ही केन्द्रित रहती हैं, क्योकि संगठित हिंदू इनको पसंद नहीं है और आजकल ये आरक्षण विरोध हिंदू समाज को टुकडों - टुकड़ो में विभाजित करने के लिए हर जगह हिन्दुओं को आरक्षण के नाम पर लड़ाकर दलितों में भी जाति खोज रहे हैं। जिस तरह आरक्षण विरोध लोग कह रहे हैं कि एक दिन भारत के हालात भी बांग्लादेश की तरह होने वाले हैं वह चिंताजनक है। इनकी यह बयानबाजी वास्तव में देश के सभी हिंदुओं के लिए चेतावनी है। यही कारण है कि योगीजी को हिन्दू समाज से कहना पड़ रहा रहे है कि "हम बटेंगे तो कटंगे"। समाज में दलितों की निंदा करने वाले वाही देश विरोधी लोग हैं जो अत्याचारियों, पापियों और माफिया की मौत पर उनके घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने जाते रहे हैं। ये लोग चाहते हैं वो देश में आरक्षण ख़त्म करने के समर्थन में नारे लगाएं लेकिन आरक्षण की दुहाई के नाम पर अपने दलितों को असहाय छोड़ दे और कट्टर पंथीयों व वफ्फ बोर्ड को मनमानी लूट करने दें। इसलिए, इन आरक्षण विरोधियों से सावधान और सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। क्योकि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, राष्ट्र तभी सशक्त हो सकता है जब हम एकजुट रहेंगे। देश और हिन्दू समाज को जातिवाद के नाम पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहना होगा। हम सभी लोकमंगल व राष्ट्रमंगल के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करें। ताकि हम सभी मिलकर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान कर सकें।

देश में जाति जनगणना पर आया संघ का बयान, कहा- राजनीतिक हथियार के तौर पर न हो इस्तेमाल

संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि जाति जनगणना में कोई समस्या नहीं है सरकार को भी योजनाओं के लिए आंकड़ों की जरूरत होती है। संघ ने कहा कि जनगणना का जाति के कल्याण के लिए इस्तेमाल हो न कि राजनीति हतियार के तौर पर इस्तेमाल हो। आरएसएस ने कहा कि यह समाज व देश की एकता-संप्रभुता के लिए अति संवेदनशील मामला है।

नई दिल्ली। जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की घेराबंदी में जुटे विपक्षी दलों से मुद्दा छिनते हुए आरएसएस ने स्पष्ट किया कि उसे इसमें कोई समस्या नहीं है। सरकार को भी योजनाओं के लिए आंकड़ों की जरूरत होती है। किसी विशेष समुदाय या जातियों के कल्याण के लिए विशेष ध्यान देने के लिए आवश्यक हो तो यह होना चाहिए। लेकिन, इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते विपक्षी दलों को चेताते हुए कहा है कि यह समाज व देश की एकता-संप्रभुता के लिए अति संवेदनशील मामला है। ऐसे में इसका इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए या राजनीतिक हथियार के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए।

विपक्ष नेता राहुल गांधी ने की है मांग

संघ का यह स्पष्ट संदेश ऐसे समय में आया है, जब जाति जनगणना की मांग में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सौंदर्य प्रतियोगिताओं तक में आरक्षण की मांग रखी है। साथ ही सरकार और संघ पर इसका विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं।

सरकार को आंकड़ों की होती है जरूरत

केरल के पलक्कड़ में आयोजित संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक के अंतिम दिन पत्रकार वार्ता में एक सवाल के जवाब में संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि सभी योजनाओं में किसी खास समुदाय या जाति पर विशेष ध्यान देने के लिए सरकार को आंकड़ों की आवश्यकता होती है। यह पहले से अच्छी तरह से प्रयोग में होता रहा है।

नहीं बनाना चाहिए राजनीतिक हथियार

आगे भी इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जनगणना का इस्तेमाल उस विशेष समुदाय या जाति के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। न कि उसे राजनीतिक हथियार या चुनावी मुद्दा बनाया जाना चाहिए। क्योंकि, यह जाति व जाति-संबंध हिंदू समाज के लिए बहुत संवेदनशील होने के साथ हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है।

संघ का शताब्दी वर्ष

आगे उन्होंने बताया कि संघ के शताब्दी वर्ष में सामाजिक परिवर्तन के लिए तय पंच परिवर्तन में देश में जाति की खाई को पाटने के लिए सामाजिक समरसता व सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम तय किए गए हैं। उसमें समाज व धर्म के प्रबुद्ध लोगों को साथ लाने की तैयारी है। संघ की तीन दिवसीय समन्वय बैठक में भाजपा, विहिप व विद्यार्थी परिषद के साथ ही संघ प्रेरित कुल 32 संगठनों के शीर्ष प्रतिनिधि जुटे थे, जिनके बीच समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे संगठनों ने अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की तथा आगे का लक्ष्य तय किया।

वाहन चालक सावधान! दूसरे राज्यों में भी हो सकता है पंजीयन निलंबित; हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने दूसरे राज्यों में भी वाहनों का पंजीयन निलंबित किए जाने को लेकर आदेश जारी किए है।

जिला परिवहन अधिकारी अब दूसरे राज्यों के वाहनों का भी अपने राज्य में पंजीयन निलंबित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक माह के भीतर संबंधित राज्य के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को इसकी सूचना भिजवानी होगी। जयपुर में वाहन का पंजीयन निलंबित करने के मामले में एमपी हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था दी, साथ ही मोटर व्हीकल नियमों को स्पष्ट किया।

आरटीओ द्वितीय धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जयपुर परिवहन कार्यालय द्वितीय के उड़नदस्ते ने एक मई 2024 को खाटूश्याम से ग्वालियर जाते हुए स्लीपर यात्री वाहन यूपी 95 टी 5127 को बस बॉडी कोड को मानकों का उल्लंघन करने पर जब्त किया। जांच के दौरान सामने आया कि वाहन में चैसिस के ऊपर और पूरे फर्श के नीचे लगभग 26 फीट लम्बी, 8 फीट चौड़ी व 2 फीट ऊंचाई की डिग्गी/डिक्की बनी थी।

इसके अतिरिक्त वाहन का चैसिस काटकर और ओवरहेंग कर पीछे की ओर लगभग 4 फीट लम्बी व 8 फीट चौड़ी अतिरिक्त डिग्गी/डिक्की बनाई हुई थी। यात्री वाहन में लगे सभी स्लीपरों की निर्धारित लम्बाई 1800 एमएम से कम गई। इसी के साथ आपातकालीन द्वार भी नहीं थे। इस पर आरटीओ-2 की ओर से बस का पंजीयन निलंबित कर दिया।

मूल पंजीयन अधिकारी को सूचना देनी होगी

वाहन मालिक ने एमपी हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा कि वाहन ग्वालियर में पंजीकृत होने के कारण जिला परिवहन अधिकारी जयपुर द्वितीय पंजीयन निलंबित नहीं कर सकता। इस पर कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए कहा कि ग्वालियर में पंजीकृत वाहन का जिला परिवहन अधिकारी जयपुर द्वितीय की ओर से पंजीयन निलंबित किया जा सकता है।

पंजीयन निलंबन की सूचना वाहन के मूल पंजीयन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी ग्वालियर को देनी होगी। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया कि किसी राज्य में पंजीकृत टूरिस्ट यात्री वाहनों का अन्य राज्यों में संचालन होने पर संबंधित राज्य के मोटर यान नियमों की पालना करनी होगी।

हाई स्पीड में वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को दिया सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136 ए को लागू करने का निर्देश जारी किया है। इसमें तेज गति से चलने वाले वाहनों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि इसका उद्देश्य राजमार्गों और शहरी सड़कों पर सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136 ए को लागू करने का निर्देश जारी किया है। इसमें तेज गति से चलने वाले वाहनों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की व्यवस्था प्रदान करती है। कोर्ट ने कहा कि इसका उद्देश्य राजमार्गों और शहरी सड़कों पर सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल को मोटर वाहन अधिनियम के नियम 167ए के साथ धारा 136ए के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों से कोर्ट को छह दिसंबर तक अवगत कराने को कहा है।

इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रानिक उपकरणों के उपयोग के बारे में निर्णय लेने के बाद यह सुनिश्चित करेंगे कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रविधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना इलेक्ट्रानिक उपकरणों के फुटेज के आधार पर लगाया जाए।

राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर उच्च जोखिम और घनी आबादी वाले क्षेत्रों और महत्वपूर्ण चौराहों पर इलेक्ट्रानिक उपकरण लगाए जाएं। इसमें कम से कम दस लाख से अधिक आबादी वाले प्रमुख शहरों को भी शामिल किया जाए।

श्री आईजी गौशाला में सोमवती अमावस्या पर गौसेवा

हैदराबाद: बालाजी नगर स्थित श्री आईजी गौशाला में सोमवती अमावस्या पर हरा घास खिलाते हुए अध्यक्ष मंगलाराम पंवार, उपाध्यक्ष कालुराम काग,सचिव हुक्माराम सानपुरा, नारायण लाल परिहार, भगाराम मुलेवा, मोतीलाल काग, नारायण लाल आगलेचा जयराम, जगदीश मालविया, भंवरलाल मुलेवा ,अर्जुन लाल बर्फा, डायाराम लचेटा, पारसमल शर्मा,कालुराम काग चितल, गोपाराम मुलेवा, मोतीलाल काग, बाबूलाल मुलेवा, पुनम चन्द्र हाम्बड़, दुर्गा प्रसाद हाम्बड़, भोजन प्रसादी जयराम परिहार,भरत, अशोक शिल्पा परिहार चंदनसिंह,छेलु सिंह राजपूत,सरदारराम सीरवी, सत्यनारायण कुमार,ओमप्रकाश , आईमाता जी भजन मण्डली बालाजी नगर द्वारा अचलाराम हाम्बड़, मोहनलाल भायल, महिला भजन मण्डली द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया।

ओडिशा में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित नहीं हो सकती है : मुख्यमंत्री मोहन माझी

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुवनेश्वर: ओडिशा में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री मोहन माझी ने विधानसभा में अपने लिखित जवाब में यह स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, ओडिशा में कहीं भी हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है।किकेश नारायण सिंहदेव ने पूछा कि क्या बलांगीर में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का प्रस्ताव है।इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन माझी ने विधानसभा में लिखित जवाब दिया है। विधायक किकेश सिंहदेव के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में दिए गए फैसले के अनुसार, ओडिशा में कहीं भी हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है।

पर्यावरण पाठशाला: पेड़ों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने के दुष्प्रभाव

परिवहन विशेष न्यूज

पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण पाठशाला और विभिन्न पर्यावरणीय स्वयंसेवकों ने देश भर में पेड़ों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अभियान शुरू किया है। पेड़ों पर कीलें ठोककर या स्टेपलर का उपयोग करके विज्ञापन बोर्ड लगाने की प्रथा न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि यह पेड़ों के लिए भी गंभीर नुकसानदायक होती है।

पेड़ों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने के दुष्प्रभाव:

पेड़ की स्वास्थ्य को नुकसान: कील या स्टेपल से पेड़ की छाल में छेद हो जाता है, जिससे पेड़ के अंदर की नमी और पोषक तत्व बाहर निकल सकते हैं। इससे पेड़ की वृद्धि पर बुरा असर पड़ता है और कभी-कभी पेड़ के सूखने का खतरा भी हो सकता है।

संक्रमण और बीमारी का खतरा: छाल में छेद होने से पेड़ में संक्रमण और फंगस की संभावना बढ़ जाती है। यह पेड़ की जीवन प्रत्याशा को कम कर सकता है और पेड़ के आसपास के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

पेड़ की संरचना पर असर: पेड़ों पर लगातार कीलें ठोकने से उनकी संरचना कमजोर हो जाती है। इससे उनकी शाखाओं के टूटने या पेड़ के गिरने की संभावना बढ़ जाती है, जो लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है।

पर्यावरण पाठशाला के तहत, इस जागरूकता अभियान में ऐसे पोस्टर्स और विज्ञापन बोर्ड को पेड़ों से हटाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही, ऐसे विज्ञापनदाता जो इस तरह के कार्यों में संलग्न पाए जाते हैं, उनकी सूची संबंधित नोडल अधिकारी को सौंपी जा रही है ताकि उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, उन सेवाओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को भी चेतावनी दी जा रही है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की पर्यावरण-विरोधी गतिविधियों से बचा जा सके।

हमारा उद्देश्य है कि समाज में पर्यावरण संरक्षण की भावना को बढ़ावा दिया जाए और पेड़ों को सुरक्षित रखा जा सके। यदि आप भी इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं या इस बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें और इस नेक कार्य में अपना योगदान दें।

अगर आपके शहर में या आस-पड़ोस में किसी भी पेड़ पर इस तरीके के विज्ञापन लगे हुए हैं और उनसे पेड़ों को नुकसान हो रहा है, तो कृपया उसकी तस्वीर खींचकर हमें ईमेल या सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करें। यह एक प्रयास है कि छोटे-छोटे खतरों से हम अपने पेड़ों की रक्षा कर सकें।

पेड़ों ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब समय आ गया है कि हम भी उनके प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाएं। पेड़ लगाएं या न लगाएं, लेकिन पेड़ों को अवश्य बचाएं। पर्यावरण पाठशाला और Indian Green Buddy के इस प्रयास में हमारा साथ दें। आइए, मिलकर पेड़ों की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाएं और उन्हें हर प्रकार के नुकसान से बचाएं।

- indiangreenbuddy@gmail.com
X@greenbuddy2024

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail .com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023